mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-06 अंक-201 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना
22 जुलाई 2026 बुधवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

हाईकोर्ट का सोनम वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने का आदेश

4 दिन से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती; जंतर-मंतर पर पुलिस के खिलाफ नारे

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मेदांता उनके इलाज के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाएगा। कोर्ट ने यह आदेश उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो की याचिका पर दिया है।

सोनम 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं। 18 जुलाई को तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस उन्हें जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। सोनम की पत्नी ने कोर्ट में याचिका लगाकर उन्हें पसंद के अस्पताल में शिफ्ट कराने की मांग की थी।

उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का जंतर-मंतर पर मंगलवार को 32वें दिन प्रदर्शन जारी है। दोपहर 12 बजे तक हजारों की संख्या में आंदोलनकारी मौजूद हैं। सुबह कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हें नाश्ता बांटा।

वांगचुक की पत्नी बोलीं- सोनम को नजरबंद किया गया: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सफदरजंग अस्पताल में उन्हें नजरबंद जैसा रखा गया था ताकि वे बाहरी लोगों से न मिल सकें। उनका कहना है कि वांगचुक की सेहत गंभीर नहीं थी और उनकी जांच जंतर-मंतर पर भी हो सकती थी।

आज सुबह जब सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पहुंची तो छात्रसमर्थकों ने हाय-हाय के नारे लगाए। इससे पहले संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार की देर शाम को जंतर-मंतर खाली करा लिया था, लेकिन आंदोलनकारी देर रात फिर एकत्रित हो गए।

दीपके ने कहा- संसद मार्च नहीं निकालेंगे, वांगचुक का अनशन जारी रहेगा

अभिजीत दीपके ने मंगलवार को कहा कि कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे। हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से इसके लिए राजी किया था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था। हमने उनसे कहा था कि सर, कृपया अनशन खत्म कर दीजिए। हम आपकी जान को अब और खतरे में नहीं डाल सकते। इस देश के लिए आपका जीवन बहुत कीमती है। वह किसी तरह मान गए थे।उन्होंने बताया कि सोमवार को हुई बर्बरता और पुलिस की कार्रवाई देखने के बाद सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है।

पेपर लीक मुद्दे पर राहुल गांधी स्पीकर से मिले

कहा: लोकसभा में चर्चा हो; खड़गे बोले- सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, चिट्ठी लिखी

नई दिल्ली,एजेंसी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित कर दी गई। इसके पहले मंगलवार सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष ने NEET पेपर लीक पर चर्चा की मांग की, प्लेकार्ड दिखाए और नारेबाजी की। भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और इसके बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई थी।सदन के बाहर आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में ऐसा करना गलत है। वहीं, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की।कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत काम रोकने का नोटिस दिया है। उन्होंने NEET व 2026 पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की है।वहीं, इससे पहले संसद भवन में NDA संसदीय दल की बैठक हुई।

: ब्रीफ बॉक्स :

भारत को रूस का ऐतिहासिक जेट इंजन ऑफर, अमेरिका हिल गया

नई दिल्ली,एजेंसी। मास्को से आई बड़ी खबर ने अंतरराष्ट्रीय रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। रूस ने अपने हाल ही में विकसित किए गए सबसे अत्याधुनिक एएल51 एफ1 जेट इंजन का एक अभूतपूर्व ऑफर भारत को दिया है, इस आफर ने अमेरिका तक को चौंका दिया है। यह केवल एक बिक्री समझौता नहीं, बल्कि भारत को स्टेल्थ पावर में आत्मनिर्भर बनाने का एक सुनहरा मौका है। एएल51 एफ1 जेट इंजन को दुनिया एक मास्टरपीस मान रही है, जिसने दशकों से अमेरिकी स्टेल फाइटर इंजन के वर्चस्व को चुनौती दी है। यह इंजन न केवल फाइटर जेट को बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक रफ्तार (सुपरक्रूज़) देता है, बल्कि इसका थ्रस्ट वेक्टरिंग और कम हीट सिग्नेचर रडार से ओझल रखने में मदद करता है। रूस ने भारत को केवल यह इंजन बेचने की बात नहीं की है, बल्कि एक व्यापक पैकेज पेश किया है।

टठटइस ऑफर में तकनीक साझाकरण (टेक शेयरिंग) शामिल है, जहाँ रूस इंजन के डिज़ाइन समाधान और विकास के अनुभव को भारत के साथ साझा करेगा। दूसरा, अगर भारत भविष्य में अपना स्टेल्थ इंजन विकसित करता है, तब रूस उसमें तकनीकी सहयोग का वादा कर रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु ब्रिज सप्लाई है जब तक भारत का अपना इंजन तैयार नहीं हो जाता, रूस एएल51 एफ1 जेट इंजन की निर्बाध आपूर्ति करेगा इस किसी भी देश द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पेशकश माना जा रहा है।

भारत अब ट्रेनी नहीं ट्रेनर: कोच्चि बना 25 देशों का नौसेना प्रशिक्षण केंद्र

'ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस' का आगाज

नई दिल्ली,एजेंसी। कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में सोमवार से चार दिवसीय बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस का आगाज हुआ। नौसेना के इस प्रशिक्षण में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (सीएमएफ) के 25 देशों की नौसेनाएं भाग ले रहीं।बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों में नौसेना की भूमिका भी नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। भारत एक प्रशिक्षु की भूमिका से आगे बढ़कर प्रशिक्षक की भूमिका में आ गया है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस बड़े प्रशिक्षण अभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सेशेल्स जैसे देशों के शीर्ष नौसैनिक और सैन्य प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कोच्चि तेजी से नौसेनाओं के लिए एक प्रमुख और आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में अपनी धाक जमा रहा है। यहां स्थित दक्षिणी नौसेना कमान के पास अत्याधुनिक नौसैनिक संस्थान, उन्नत सिमुलेटर और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान देता है। यही वजह है कि नियमित और उच्चस्तरीय सैन्य प्रशिक्षण के लिए दुनियाभर की नौसेनाएं कोच्चि का रुख करती हैं।

सिक्किम की निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, 10 मजदूरों की मौत

17 अब भी फंसे; मलबे से सुरंग बंद, रेस्क्यू करने गए कुछ वर्कर बेहोश

गंगटोक,एजेंसी। सिक्किम में सोमवार को एक टनल पर लैंडस्लाइड होने से उसका एंट्री गेट बंद हो गया, जिससे अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 की मौत हो गई। मृतकों में 3 की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जबकि 17 मजदूर अब भी फंसे हैं।

नामची जिले के मामरिंग स्थित समरदुंग सुरंग में निर्माण कार्य चल रहा था। एसपी सोनम डोल्मा ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों की संख्या 27 से कम या ज्यादा भी हो सकती है।सुरंग में मीथेन गैस लीक होने की आशंका है। कई बचावकर्मियों को अंदर जाने के दौरान चक्कर आए। कुछ बेहोश भी हो गए, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ।

बंगाल से स्पेशल रेस्क्यू टीम लाई गई: जिला अधिकारी तमलिंग ने बताया कि दोपहर करीब 3:40 बजे प्रशासन को हादसे की खबर मिली। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई।सुरंग में पटेल इंजीनियरिंग के 21 और एनएचपीसी के 6 समेत कुल 27 मजदूर फंसे होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल से भी गैस-रोधी उपकरणों के साथ एक स्पेशल रेस्क्यू टीम लाई गई है।

एंबुलेंस को तैयार रखा गया है। बचाव दल गैस मास्क पहनकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है।

नगालैंड: बाढ़-भूस्खलन से नौ लोगों की मौत, मलबे में तब्दील हुए कई घर; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

कोहिमा,एजेंसी। नगालैंड के मोन जिले में लगातार बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। राज्य सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को पांच और शव बरामद किए गए, जबकि चार लोग अब भी लापता हैं और उन्हें ढूढ़ने के लिए खोज एवं बचाव अभियान जारी है।लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नुकसान का आकलन अभी जारी है और तबाही के आंकड़े आगे और बढ़ने की आशंका है।जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य भर में बारिश के इस कहर से कम से कम 7,460 लोग प्रभावित हुए हैं।

ट्रेड डील का विरोध: पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच स्थगित

हरियाणा में बॉर्डर सील, किसान नेता, सीजेपी समर्थक हाउस अरेस्ट; कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर जाम

गुरुग्राम,एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद घेराव और किसानों की प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए हरियाणा के पंजाब, दिल्ली और यूपी से लगे बॉर्डरों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कई जिलों में किसान नेताओं और CJP समर्थकों को हाउस अरेस्ट या डिटेन किया गया है।अमेरिका-भारत फ्री ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के किसानों ने मंगलवार को दिल्ली के किसान घाट जाने के लिए कूच का ऐलान किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सख्ती और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया।भारतीय किसान यूनियन कितना संघर्ष प्रदेश जनरल सेक्रेटरी दिलबाग सिंह दिराजके ने कहा- किसानों की अरेस्ट किए गए किसान नेताओं को छोड़ने व केंद्र सरकार से मीटिंग की मांग

थी।जिसमें दोनों मांगों पर सहमति बन गई। इसलिए अब धरना स्थगित कर रहे हैं।

रोहतक, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, झज्जर, पानीपत और करनाल समेत 12 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर 27 जुलाई तक धारा 163 लागू कर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई।

वहीं, सोनीपत के कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हरियाणा पुलिस ने वज्र वाहन तैनात कर वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है।

अमेरिका ने माना- ईरानी हमलों में 100 सैनिक घायल

कहा: सुरक्षा को देखते हुए देर से जानकारी दी

अमेरिका का 9 ईरानी शहरों पर हमला

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। अमेरिका ने मान लिया है कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके करीब 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सैनिक 7 जुलाई के बाद हुए हमलों में घायल हुए। इनमें से 96% सैनिक ठीक होकर ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर को हल्की सिर की चोट (कनकशन) लगी थी।

पार्नेल ने यह बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के जवाब में दिया, जिसमें दावा किया गया था कि रक्षा मंत्रालय ईरान के साथ युद्ध में घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। पार्नेल ने कहा कि इसमें जानबूझकर देरी हुई। ऐसा सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया।

उधर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमले जारी हैं। ईरान ने सोमवार को उन देशों को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने मंगलवार सुबह ईरान के 9 शहरों पर हवाई हमले किए।

ईरान की लेबर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अबदानान, बंदर अब्बास, बंदर लेंगेह, बुशेहर, चाबहार, केश्म द्वीप, सीरिक, शीराज और कोनारक को निशाना बनाया गया।

ईरान में पेट्रोल महंगा करने पर विचार

ईरान की संसद के सदस्य मोहम्मद बहश्ती गाजी ने कहा है कि सरकार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उनके मुताबिक, सरकार का मानना है कि मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि जंग की वजह से सरकारी आय पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है।गाजी ने कहा कि ईंधन की कीमतों पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है और इस मुद्दे पर संसद तथा सरकार के बीच बातचीत जारी है। ईरान में पेट्रोल की कीमतें भारतीय रुपए के हिसाब से 1 रुपए प्रति लीटर के करीब है। यह दुनिया के सबसे सस्ता है, क्योंकि सरकार उस पर भारी सब्सिडी देती है।हालांकि, ईरान में पेट्रोल की कीमत बढ़ाना राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। 2019 में पेट्रोल की कीमत बढ़ाए जाने के बाद देशभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हिंसा हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इसी वजह से मौजूदा सरकार भी इस मुद्दे पर सावधानी बरत रही है।

चेन्नई में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सेवानिवृत्त आरटीओ अधिकारी और कारोबारी के ठिकानों पर छापे

चेन्नई ,एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह चेन्नई में बड़ी कार्रवाई करते हुए तेनामपेट और तिरुवोट्टियूर क्षेत्र में दो स्थानों पर छापेमारी की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में ईडी की टीम ने एक सेवानिवृत्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के उप आयुक्त और एक कारोबारी के ठिकानों की तलाशी ली। अचानक हुई इस कार्रवाई से प्रशासनिक और कारोबारी हलकों में हलचल मच गई।

कड़ी सुरक्षा के बीच घंटों चली तलाशी

ईडी अधिकारियों ने दोनों परिसरों को चारों ओर से घेरकर प्रवेश और निकास पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। इसके बाद टीम ने घरों के कमरों, अलमारियों, दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की गहन जांच की। कार्रवाई के दौरान दोनों संबंधित व्यक्ति अपने-अपने आवास पर मौजूद रहे।

राम-मंदिर चढ़ावा चोरी: योगी ने नई एसआईटी को मंजूरी दी

आईएएस की जगह 2 आईपीएस होंगे शामिल; ट्रस्ट की बैठक में 3 सदस्यों पर चर्चा होगी

अयोध्या,एजेंसी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आज संसद भवन में हंगामे के आसार हैं। वहीं कल यानी 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में सदस्यों की कमी पर विचार किया जाएगा। SIT की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा होगी। सीईओ तैनाती समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की जाएगी।

वहीं सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा SIT बनाने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कहा- नए सिरे से SIT बनाई जाए। सीनियर IPS अधिकारी टीम की अगुआई करें, ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर तक पहुंचे।

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता को यूपी सरकार से स्ट्रक्चर के लिए नाम लेकर आने को कहा। अदालत अब 27 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी।

जबकि सोमवार शाम सीएम योगी ने नई SIT बनाने की मंजूरी दे दी है। नई SIT में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव नीलरतन कुमार नहीं होंगे। उनकी जगह एक DIG और एक SSP स्तर के IPS अधिकारी को शामिल किया जाएगा। SIT पहले से दर्ज FIR पर मामले की जांच करेगी। 30 जुलाई तक SIT अपनी रिपोर्ट देगी।

चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी जेल में, अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप

चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने 25 जून को FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसी दिन रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में सभी फैजाबाद जेल में हैं। इन सभी पर चढ़ावा गिनती करते वक्त नोटों और गहनों की चोरी का आरोप है। उधर, SIT ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा को चढ़ावा चोरी के लिए जिम्मेदार माना है। आरोप है कि उन्होंने चढ़ावा गिनती की प्रक्रिया में लापरवाही बरती। तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

मानसरोवर में डुबकी नहीं, बाल्टी से हो रहा स्नान

2018 से चीनी रोक बरकरार; कैलाश परिक्रमा में टॉयलेट की कमी से बढ़ी मुश्किलें

पिथौरागढ़,एजेंसी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र मानसरोवर झील में डुबकी लगाने की अनुमति नहीं है। चीनी प्रशासन ने मानसरोवर झील को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए झील में उतरकर स्नान करने पर प्रतिबंध लगा रखा है।

ऐसे में श्रद्धालु झील से बाल्टी में पानी निकालकर स्नान कर धार्मिक परंपरा निभाते हैं। वहीं कैलाश परिक्रमा के दौरान डेरापुक और झुंझुपुई में शौचालयों की कमी से यात्रियों, खासकर महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हर यात्री को मिलती है एक बाल्टी

कैलाश पर्वत के दर्शन के बाद मानसरोवर झील में डुबकी लगाना सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा मानी जाती है। लेकिन वर्ष 2018 के बाद चीनी प्रशासन ने झील में उतरकर स्नान करने पर रोक लगा दी। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला मानसरोवर झील को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लिया गया है।इस वर्ष भी यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को शुरुआत में ही एक-एक बाल्टी दी गई। श्रद्धालुओं ने उसी बाल्टी से मानसरोवर का जल निकालकर स्नान किया और धार्मिक परंपरा पूरी की।

दिल्ली रिक्शा गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उम्रकैद की सजा घटाकर की 20 साल

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी की सजा को कम कर दिया है. कोर्ट ने उसे 'बाकी बची पूरी जिंदगी जेल में काटने' की सजा की जगह 'छूट के साथ 20 साल के कारावास' की सजा सुनाई है. हालांकि, कोर्ट ने इस फैसले के साथ एक सख्त चेतावनी भी दी कि पुरुष-प्रधान (पितृसत्तात्मक) सोच आज भी महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों की मुख्य वजह बनी हुई है. न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, 'पुरुष-प्रधान सोच की बेड़ियों को तोड़ने के लिए सामाजिक और मानसिक स्तर पर काफी बदलाव आने के बावजूद, इस तरह की घटनाएं आज भी बिना किसी डर या शर्म के लगातार हो रही हैं. ' पीठ ने आगे कहा, 'कानून में पिछले कुछ वर्षों में कई तरह के सुधार और संशोधन किए गए हैं, और भले ही उनका कुछ हद तक सकारात्मक असर पड़ा हो, लेकिन ऐसे अपराधों को जड़ से खत्म करने की तत्परता को थोड़ा भी कम नहीं किया जा सकता. हमें तब तक प्रयास जारी रखने होंगे जब तक कि ये घटनाएं केवल इतिहास का हिस्सा न बन जाएं और पूरा समाज इन्हें नफरत की नजर से न देखने लगे. ' पीठ ने अपराध की गंभीरता को बरकरार रखते हुए, 2016 के सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए याचिकाकर्ता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया. पीठ ने कहा, 'ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और दोषी-अपीलकर्ता के पक्ष में पहले नोट किए गए कारणों पर विचार करते हुए, हम उसकी सजा को बदलकर छूट के लाभ के साथ 20 साल करना उचित समझते हैं. इस प्रकार, याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है. ' अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने 'आनुपातिकता के सिद्धांत' का हवाला दिया और कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो अपराध को रोकने, समाज की सुरक्षा करने और दोषी के सुधरने की संभावना के बीच एक सही संतुलन बनाए रखे. पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि इस मामले में दोषी का पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है. जब यह अपराध हुआ तब उसकी उम्र केवल 25 साल थी. इतनी कम उम्र होने के कारण उसके सुधरने की पूरी गुंजाइश है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि इस व्यक्ति का सुधरना नामुमकिन है. साथ ही, सरकार दोषी की इस दलील को भी नहीं काट सकी कि जेल में बिताए गए पिछले लगभग 10 सालों (छूट मिलाकर) के दौरान उसका आचरण और व्यवहार बेहद अच्छा रहा है. पीठ ने कहा कि चाहे जो भी हो, वह इस तथ्य से आंखें नहीं मूंद सकती कि यह अपराध, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बेहद जघन्य है और यह न केवल पीड़िता के खिलाफ बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है. पीठ ने कहा कि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस धारा (आईपीसी की धारा 376डी) के तहत अपीलकर्ता को सजा सुनाई गई है, उसे 2013 के आपराधिक कानून संशोधन (2013 का अधिनियम 13) के जरिए बदला गया था. यह सख्त कानून राजधानी की सड़कों पर हुई भयावह 'निर्भया' घटना के बाद लाया गया था. पीठ ने स्पष्ट किया कि इस अपराध के लिए न्यूनतम सजा बीस साल है, और अधिकतम सजा वही है जो इस अपीलकर्ता-दोषी पर लगाई गई थी यानी उसकी बची हुई पूरी प्राकृतिक जिंदगी के लिए आजीवन कारावास. अदालत ने कहा, 'यह बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देता है कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए, विधायिका (संसद) ने पहले तो इसे एक स्वतंत्र अपराध बनाया और फिर इसके लिए एक न्यूनतम सजा का प्रावधान भी किया. इसलिए, अदालत के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है और दोषी ठहराए जाने पर उसे कम से कम न्यूनतम सजा तो देनी ही होगी. ' शीर्ष अदालत ने दोहराया कि सजा का उद्देश्य दंडात्मक, अपराध रोकने वाला और सुरक्षात्मक होना चाहिए. लेकिन यह जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति जैसे अप्रासंगिक विचारों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो सकती. नई दिल्ली के आई.पी. एस्टेट थाने में एक फोन आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो आरोपियों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है. पीड़िता ने रात के समय दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस भरोसे पर एक रिक्शा लिया था कि ड्राइवर उसे उसके घर छोड़ देगा. लेकिन ऐसा करने के बजाय, वह उसे एक सूनसान जगह पर ले गया जहां एक दूसरा व्यक्ति पहले से मौजूद था. फिर उन्होंने मिलकर बलात्कार के इस अपराध को अंजाम दिया।

तेलंगाना को मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए केंद्र ने 11 करोड़ रुपये जारी की

नई दिल्ली , एजेंसी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2023 से तेलंगाना में ह्युमन-वाइल्ड लाइफ संघर्ष के प्रबंधन के लिए 11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है. लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या पिछले तीन वर्षों में तेलंगाना को मानव-पशु संघर्षों के निवारण के लिए कोई केंद्रीय सहायता दी गई है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को इस राशि का खुलासा किया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ह्युमन-वाइल्ड लाइफ संघर्ष के निवारण सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की जिम्मेदारी है. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन किसी भी संघर्ष की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं और वे संघर्ष के विवरण के साथ-साथ उसमें शामिल प्रजातियों का रिकॉर्ड रखते हैं. उन्होंने निचले सदन में कहा, 'वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, तेलंगाना राज्य को वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के दौरान क्रमशः 323.32 लाख रुपये, 291.68 लाख रुपये, 302.34 लाख रुपये और 208.67 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिसका उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष का प्रबंधन करना है. ' यादव ने कहा कि उक्त योजना के तहत समर्थित गतिविधियों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, सौर ऊर्जा संचालित विद्युत बाड़, जैव-बाड़, खाइयां, सीमा दीवारें आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण और स्थापना शामिल है, ताकि जंगली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान को रोका जा सके, जिसमें अन्य बातों के अलावा मवेशी चोरी, फसलों को नुकसान, जान-माल की हानि शामिल है. उन्होंने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सामुदायिक संरक्षकों के साथ त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'भारत सरकार ने तेलंगाना सहित पूरे देश में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति का आकलन किया है, विशेष रूप से बाघों और हाथियों जैसी प्रमुख प्रजातियों के संदर्भ में. पिछले एक दशक में तेलंगाना राज्य में हाथियों के हमले से किसी भी मानव की मृत्यु नहीं हुई है और बाघों के हमले से केवल तीन मानव मृत्यु दर्ज की गई हैं. ' एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, 'मुआवजे और प्रभावित जिलों से संबंधित विस्तृत आंकड़े राज्य स्तर पर संकलित किए जाते हैं.' मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने अंतर-विभागीय समन्वित कार्रवाई के माध्यम से मानव-वन्यजीव नकारात्मक अंतःक्रियाओं के प्रबंधन के लिए सलाह और दिशानिर्देश जारी किए हैं, साथ ही इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन सुनिश्चित किया है. मंत्री जी ने बताया कि मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना सलीम अली पक्षीविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (सैकॉन), डब्ल्यूआईआई-दक्षिण भारत केंद्र, कोयंबटूर में की है।

इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री, सवाल उठाने पर मिली लाठी: राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी। सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में संसद तक मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और

सुरक्षाबलों के बीच झड़प की घटनाएं भी सामने आईं। कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़े। सरकार की कार्रवाई के बाद विपक्ष ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मंत्री को देश के इतिहास में सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री करार दिया।

प्रधानमंत्री मोदी को बताया युवा विरोधी प्रधानमंत्री: प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक। 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित। और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। राहुल गांधी ने लिखा कि लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उनपर टूट पड़ी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार की कार्रवाई और युवाओं के प्रदर्शन पर सरकार को घेरते हुए अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कविता पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि निराशा में आंख का पानी, जब समुंदर बन जाता है। 'इंकलाब' तब आता है, कोई अपनी ताकत पर। जब सर उठा इठलाता है, 'इंकलाब' तब आता है। हुकूमतों का घमंड-गुरूर, जब पर्वत सा बन जाता है। 'इंकलाब' तब आता है।

सरकार अपनी अक्षमताओं की करे समीक्षा: प्रियंका गांधी: वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार को बच्चों पर लाठी चलाने की जगह अपनी नीतियों और अक्षमताओं की समीक्षा करनी चाहिए। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और ऋ्क्ष-ह्श्वश्वञ्ज में भी गड़बड़ी की खबरें आई हैं। आगे उन्होंने कहा कि कहा गया था कि प्रधानमंत्री खुद निगरानी करेंगे, इसके बावजूद यह सब क्यों और कैसे हो रहा है? बार-बार इतने पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को देश के करोड़ों युवाओं की बात सुननी चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए।

परिसीमन बिल पर शरद पवार की पार्टी में मतभेद, सुप्रिया सुले और रोहित पवार के अलग-अलग सुर

मुंबई, एजेंसी। केंद्र की मोदी सरकार के परिसीमन बिल को लेकर शरद पवार की राकां में दो-फाड़ हो गया है। एक ओर जहां पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर उनकी मांगें मानी गई तो समर्थन देने पर विचार किया जा सकता है, जबकि पार्टी के विधायक रोहित पवार ने नसीहत देते हुए कहा कि हमें बीजेपी सरकार के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल को संसद में पास कराने के लिए बीजेपी सरकार विपक्ष की सहमति हासिल करने के लिए कई तरह का प्रलोभन देगी। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि परिसीमन बिल संसद के मानसून सत्र में लाकर पास कराया जाएगा।

लोस सीटों को 50% बढ़ाने की मांग: सुप्रिया सुले ने कहा है कि हमारी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन करने पर विचार कर सकती है, अगर सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ा दी जाए। हालांकि सोमवार को उनके भतीजे रोहित पवार ने एक अलग रुख अपनाया, और सभी सांसदों से बिल का विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार अपनी रणनीति के तहत परिसीमन बिल को पास कराने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी का ऑफर दे सकती थी लेकिन अगर हम नंबरों के इस जाल में फंस जाते हैं और बिल को सपोर्ट करते हैं तो इसके बाद म्युनिसिपल वार्ड की तर्ज पर लोकसभा व विधानसभा सीटों को मैनिपुलेट किया जाएगा।

राजनीतिक चर्चा तेज: परिसीमन बिल को लेकर एनसीपी (शरद पवार) के वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग बयानों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। अब राजनीतिक दलों की नजर इस बात पर रहेगी कि संसद में बिल पेश होने के दौरान विपक्ष का अंतिम रुख क्या रहता है और इस मुद्दे पर दलों के भीतर बनी राय किस दिशा में जाती है।

डीयू का बड़ा फैसला: रैगिंग पर सख्त पहरा, नॉर्थ-साउथ कैंपस में बनेंगे संयुक्त कंट्रोल रूम

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले रैगिंग पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों, विभागों, छात्रावासों, डूसू पदाधिकारियों और दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर कई अहम फैसले लिए हैं. नए छात्रों के लिए सुरक्षित और भयमुक्त माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नॉर्थ और साउथ कैंपस में संयुक्त कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा कॉलेजों में एंटी-रैगिंग कमेटियां सक्रिय रहेंगी, पुलिस निगरानी बढ़ाई जाएगी और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. विश्वविद्यालय ने साफ कहा है कि रैगिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी. डीयू के प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से 20 जुलाई को एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी कॉलेजों के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, छात्रावास अधीक्षक, डूसू के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी शामिल हुए. बैठक का उद्देश्य नए छात्रों के प्रवेश के दौरान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और रैगिंग की घटनाओं को पूरी तरह रोकना था. बैठक में सभी कॉलेजों और विभागों को निर्देश दिए गए कि नए छात्रों के साथ किसी भी तरह का उत्पीड़न या रैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि किसी छात्र की शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

नॉर्थ और साउथ कैंपस में बनेंगे कंट्रोल रूम: विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि

नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में एक-एक संयुक्त कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. ये कंट्रोल रूम 28 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक लगातार 24 घंटे सक्रिय रहेंगे. यहां विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया जा सके. नए छात्र और उनके अभिभावक भी किसी परेशानी की स्थिति में इन कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकेंगे.

कॉलेजों और हॉस्टलों में रहेगी विशेष निगरानी: डीयू ने सभी कॉलेजों, विभागों और छात्रावासों को एंटी-रैगिंग कमेटी, एंटी-रैगिंग स्क्वॉड और अनुशासन समिति सक्रिय रखने के निर्देश दिए हैं. ये टीमें नए छात्रों से नियमित संपर्क रखेंगी और परिसर में लगातार निगरानी करेंगी. जहां जरूरत होगी वहां एनसीसी, एनएसएस और छात्र स्वयंसेवकों की भी मदद ली जाएगी. सभी कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि परिसर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एंटी-रैगिंग पोस्टर और बैनर लगाए जाएं. नए छात्रों को प्रवेश के समय रैगिंग विरोधी नियमों और शिकायत प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी।

दिल्ली पुलिस भी देगी पूरा सहयोग

बैठक में दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया. कॉलेजों और छात्रावासों के आसपास नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी. जरूरत पड़ने पर पुलिस पिकेट भी लगाए जाएंगे. महिला कॉलेजों और छात्रावासों के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

रैगिंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि रैगिंग के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. यदि कोई छात्र रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ निलंबन, निष्कासन, छात्रावास से बाहर करना, प्रवेश रद्द करना, परीक्षा से वंचित करना और डिग्री रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है. गंभीर मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि यदि उनके साथ या उनके किसी साथी के साथ रैगिंग होती है ।

नए पीएम के आते ही उप-प्रधानमंत्री का डेविड लैमी इस्तीफा, ब्रिटेन सियासी हलचल तेज जाते-जाते दी बड़ी चेतावनी

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार का गठन शुरू हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद एंडी बर्नहैम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाल लिया। नई कैबिनेट बनने के बीच ब्रिटेन के उप-प्रधानमंत्री डेविड लैमी ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लैमी ने कहा कि नए प्रधानमंत्री को अपनी पसंद की टीम चुनने का पूरा अधिकार है। लैमी ने भरोसा दिलाया कि वह सांसद के रूप में लेबर पार्टी और सरकार का समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि टोटेनहैम से निकलकर विदेश सचिव, न्याय सचिव और पहले अश्वेत उप-प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करना उनके लिए गर्व की बात रही। इस्तीफे पर क्या बोले डेविड लैमीः श्रडेविड लैमी ने कहा कि विदेश सचिव के रूप में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर काम किया। उनके मुताबिक ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय देशों के साथ ब्रिटेन के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने यूक्रेन के समर्थन, वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने, फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने की दिशा में उठाए गए कदमों और अमेरिका, भारत तथा खाड़ी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि इन कदमों का उद्देश्य ब्रिटेन की सुरक्षा और आर्थिक हितों को मजबूत करना था। अपने बयान में डेविड लैमी ने न्याय सचिव के तौर पर किए गए कामों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अदालतों में रिकॉर्ड निवेश किया गया ताकि लंबित मामलों की संख्या कम हो सके।

ईरान: सुन्नी धर्मगुरु मोहम्मद अनवर रिगी की हत्या, मस्जिद के पास अज्ञात बंदूकधारियों ने मारी गोली

तेहरान, एजेंसी। ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत स्थित मिर्जावेह शहर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहाँ अज्ञात बंदूकधारियों ने प्रमुख बड़े सुन्नी मौलवी मोहम्मद अनवर रिगी की हत्या कर दी है। मौलवी रिगी शहर की मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के इमाम थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सरकारी मीडिया ने स्थानीय अधिकारियों का हवाला देते हुए इस घटना की पुष्टि की है। यह क्षेत्र पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है और भौगोलिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता है। सिस्तान-बलूचिस्तान ईरान का सबसे गरीब और अशांत प्रांतों में से एक है। शिया-बहुल ईरान में यह प्रांत सुन्नी बलूच आबादी का गढ़ है, जो लंबे समय से जातीय और इस्लामी उग्रवादियों तथा सुरक्षा बलों के बीच जारी संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने इस हमले को प्रांत की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की एक सोची-समझी

साजिश बताया है। फिलहाल, अधिकारी मामले की गहन जांच कर रहे हैं और उन्होंने आम जनता से संयम बरतने व शांति बनाए रखने की अपील की है। मौलवी की हत्या ने इस सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है।

अज्ञात बंदुकधारियों ने की धर्मगुरु की हत्या: आपको बता दें कि सुन्नी धर्मगुरु अनवर रिगी की जब हत्या की गई तो ईरान के स्थानीय समय के अनुसार वहां सुबह के 4 बज रहें थें।

न्यूयॉर्क फेडरल बिल्डिंग हमला: पूर्व अमेरिकी सैनिक ने ही लगाई आग; क्या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी आतंकी साजिश

न्यूयॉर्क , एजेंसी। क्या न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक पर हमला किसी बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था? न्यूयार्क में सोमवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब 26 फेडरल प्लाजा स्थित सरकारी इमारत के बाहर एक शख्स ने अंधाधुंध पटाखे चलाए और सीढ़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस इमारत में आव्रजन अदालत और एफबीआई कार्यालय समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर हैं। एफबीआई के न्यूयॉर्क फील्ड ऑफिस के सहायक निदेशक जेम्स बार्नेकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान एंड्रयू अराबाका के रूप में हुई है, जो एक पूर्व अमेरिकी सैनिक है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

हमलावर के पास से क्या-क्या मिला और उसका इरादा क्या था:

जांच एजेंसियों के मुताबिक, आरोपी एंड्रयू अराबाका बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ वहां पहुंचा था। बार्नेकल ने बताया कि वह लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के इरादे से हथियारों से लैस होकर आया था। पुलिस ने उसके पास से एक पेलेट गन (एयरसॉफ्ट राइफल), कई चाकू, एक हथौड़ा और एक धारदार हथियार बरामद किया है। उसने इमारत की तरफ एयरसॉफ्ट राइफल से पांच से सात पेलेट भी दागे। शुरुआती जांच के बाद एफबीआई अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह एक अमेरिका-विरोधी और सरकार-विरोधी चरमपंथी है। उसके पास से इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट विरोधी सामग्री भी मिली है।

वारदात की पांच बड़ी बातें: पूर्व सैनिक का खौफनाक कदमः न्यूयॉर्क की फेडरल बिल्डिंग के बाहर आग लगाने वाला आरोपी एंड्रयू अराबाका पूर्व अमेरिकी सैनिक निकला। घातक हथियारों का जखीराः हमलावर के बैग से पेलेट गन, चाकू, हथौड़ा, माचे और ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया। सरकार विरोधी मानसिकताः एफबीआई ने आरोपी को पूरी तरह से अमेरिका-विरोधी और सरकार-विरोधी चरमपंथी करार दिया है। जांबाज सुरक्षाकर्मी ने दबोचाः सीढ़ियों पर आग लगाते ही मुस्तैद सुरक्षाकर्मी ने आरोपी को जमीन पर पटक कर हिरासत में ले लिया।

हाई-प्रोफाइल निशाना: जिस 26 फेडरल प्लाजा इमारत को निशाना बनाया गया, वहां खुद एफबीआई का दफ्तर और इमिग्रेशन कोर्ट स्थित है।

ऐसे दबोचा गया आरोपी: यह घटना सुबह करीब 8:20 बजे की है। गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार, आरोपी ने इमारत के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर गैसोलीन उड़ेलकर आग लगा दी। जैसे ही लपटें उठीं, वहां तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया। इस दौरान एक राहगीर पटाखों की चपेट में आकर आंशिक रूप से झुलस गया, जबकि आरोपी को पकड़ने वाले सुरक्षाकर्मी को भी मामूली चोटें आई हैं। दमकल विभाग ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे बेहद परेशान करने वाला बताया है।

जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर छात्राएं

एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा कन्या प्राथमिक विद्यालय

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। नगर के एकमात्र कन्या प्राथमिक विद्यालय की स्थिति इन दिनों गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रही है, जबकि भवन की हालत भी अत्यंत जर्जर हो चुकी है। ऐसे में यहां अध्ययनरत छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा, दोनों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जानकारी के अनुसार विद्यालय में वर्तमान में शिक्षक शिवनाथ आदिवासी पदस्थ हैं। उनका स्थानांतरण रायपुर सोनौरी से हुआ और उन्होंने 9 जुलाई को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि अब तक उन्हें प्रशासनिक रूप से विद्यालय का प्रभारी नहीं बनाया गया है। विभागीय पोर्टल पर अभी भी सेवानिवृत्त शिक्षिका गीता द्विवेदी का नाम प्रभारी के रूप में दर्ज है। उल्लेखनीय है कि गीता द्विवेदी लगभग दो माह पूर्व सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, लेकिन विभागीय अभिलेखों में अब तक संशोधन नहीं किया गया है। विद्यालय भवन की स्थिति भी बेहद खराब है। छत से बारिश का पानी टपकता है, कई स्थानों पर सरिया बाहर दिखाई दे रही है तथा दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन किसी भी समय बड़ा हादसा होने का कारण बन सकता है। ऐसे जर्जर भवन में छात्राओं को पढ़ाना उनकी सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विद्यालय में कक्षा पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई होती है, लेकिन पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी केवल एक शिक्षक पर है। शिक्षक को शिक्षण कार्य के साथ-साथ कार्यालयीन कार्य, अभिलेख संधारण, मध्यान्ह भोजन की निगरानी तथा अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। विद्यालय में न चपरासी है और न ही चौकीदार। परिणामस्वरूप एकमात्र शिक्षक को सफाई व्यवस्था से लेकर विद्यालय संचालन तक सभी कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब शिक्षक को किसी विभागीय बैठक, प्रशिक्षण या अन्य शासकीय कार्य के लिए विद्यालय से बाहर जाना पड़ता है अथवा अवकाश लेना पड़ता है। ऐसे समय विद्यालय पूरी तरह शिक्षकविहीन हो जाता है और छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होती है। इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं बीआरसी त्योंथर से चर्चा किए जाने पर कोई स्पष्ट जानकारी या ठोस पहल सामने नहीं आ सकी। स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों का कहना है कि नगर के सबसे पुराने कन्या प्राथमिक विद्यालय की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उनका आरोप है कि वर्षों से शिक्षक और भवन संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। अभिभावकों ने शासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि विद्यालय भवन की तत्काल मरम्मत अथवा नए भवन का निर्माण कराया जाए। साथ ही छात्राओं की संख्या के अनुरूप अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इसका सीधा असर क्षेत्र की गरीब छात्राओं के भविष्य पर पड़ेगा।

अस्पताल चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा

गाय से टकराई बाइक, मिनी ट्रक के नीचे आने से युवक की मौत

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शहर के अस्पताल चौक पर सोमवार देर रात करीब 11 बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील साकेत के रूप में हुई है, जो पेशे से टाइल्स लगाने का काम करता था। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सुनील साकेत देर रात काम खत्म कर बाइक से अपने घर लौट रहा था। अस्पताल चौक के पास वह ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे एक मिनी ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक सड़क किनारे खड़ी गाय से टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और युवक सीधे मिनी ट्रक के नीचे जा गिरा। हादसा इतना गंभीर था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कुछ समय तक अस्पताल चौक पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे मिनी ट्रक को जब्त कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सड़क किनारे खड़ी गाय से टक्कर के बाद युवक के ट्रक के नीचे आने की बात सामने आई है। पुलिस ने लोगों से सड़क पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

जनसुनवाई में गूंजी महिला कर्मचारी और विधवा की पीड़ा, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

अनूपपुर (निप्र)। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 44 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें जिला अस्पताल की एक महिला कर्मचारी तथा ग्राम धनगवां की एक विधवा महिला की शिकायत प्रमुख रूप से सामने आई। कलेक्टर ने दोनों मामलों में जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। जिला अस्पताल में पिछले 14 वर्षों से कलेक्टर दर पर कार्यरत एवं वर्तमान में एमटीएस के रूप में सेवाएं दे रही महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया कि पिछले एक माह से उस पर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) में ड्यूटी करने का दबाव बनाया जा रहा है। जबकि उसकी नियमित एमटीएस ड्यूटी नहीं लगाई जा रही। महिला का कहना है कि उसके प्रभारी स्टाफ की कमी का हवाला देकर उसे रिलीव नहीं कर रहे हैं। वहीं उपस्थिति रजिस्टर में पहले उसकी उपस्थिति दर्ज की जाती है, लेकिन बाद में अज्ञात लोगों द्वारा ओवरराइटिंग कर उसे अनुपस्थित दिखाया जा रहा है। महिला के अनुसार पिछले 21 दिनों से उसकी उपस्थिति लगातार अनुपस्थित दर्ज की गई है। दूसरे मामले में ग्राम धनगवां निवासी सावित्री देवी राठौर ने अपने पति पुरुषोत्तम राठौर की 11 दिसंबर 2023 को हुई मृत्यु के बाद मिलने वाली दो लाख रुपये की मृतक सहायता राशि दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि संबल योजना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज ग्राम पंचायत के सरपंच को जमा किए थे लेकिन अब तक सहायता राशि नहीं मिली। उनका आरोप है कि सरपंच द्वारा बार-बार अलग-अलग जानकारी देकर उन्हें गुमराह किया गया और अब सहायता राशि न मिलने की बात कही जा रही है। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 42 अन्य आवेदकों ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर को सौंपे, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

पहली ही बारिश में बह गए 30 लाख के दो चेकडैम, ग्रामीणों ने जांच की उठाई मांग

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले की जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत बेलगांव ग्राम पंचायत में करीब 30 लाख रुपये की लागत से निर्मित दो चेकडैम पहली ही बारिश में बह जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। शिकायतकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सरकारी राशि के उपयोग और मजदूरों के बकाया भुगतान की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। ग्रामीणों के अनुसार, हाड़ीहिया नाला पर लगभग 15-15 लाख रुपये की लागत से दो चेकडैम का निर्माण कराया गया था। इन संरचनाओं का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण, भूजल स्तर में वृद्धि और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। लेकिन निर्माण पूरा होने के कुछ ही महीनों बाद पहली बारिश का दबाव भी दोनों चेकडैम नहीं झेल सके और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इससे शासन को लाखों रुपये की आर्थिक क्षति हुई, वहीं ग्रामीणों को योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया। शिकायतकर्ता महेश कुमार प्रजापति ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। उनका कहना है कि चेकडैम निर्माण में आवश्यक लोहे की सरिया का उपयोग नहीं किया गया तथा घटिया गुणवत्ता की निर्माण सामग्री लगाई गई। इसी कारण पहली ही बारिश में दोनों संरचनाएं बह गईं। उन्होंने पूरे मामले की तकनीकी एवं वित्तीय जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की है। ग्रामीणों ने अपनी शिकायत में निर्माण कार्य से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है। इनमें कार्य की स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका (एमबी), गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, बिल, वाउचर और भुगतान संबंधी अभिलेख शामिल हैं। साथ ही तत्कालीन सरपंच सुरेंद्र सिंह, पंचायत सचिव शिवराज सिंह तथा रोजगार सहायक जगजीवन जायसवाल की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि सात दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच शुरू नहीं की गई तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उनका कहना है कि सरकारी धन से किए गए विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होना आवश्यक है।

तेज बारिश में ढहा शासकीय परिसर का हिस्सा, छह दुकानें क्षतिग्रस्त, बड़ा हादसा टला

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। शहर में सोमवार देर रात हुई तेज बारिश के बीच एक शासकीय परिसर का हिस्सा भरभराकर गिर गया। यह हादसा गायत्री मंदिर के पास छत्रसाल स्टेडियम के सामने वार्ड क्रमांक-5 में रात करीब 1 बजे हुआ। परिसर से लगी छह दुकानों का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय सभी दुकानें बंद थीं और आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण भवन की दीवारें कमजोर हो गई थीं। अचानक तेज आवाज के साथ शासकीय परिसर का सामने का हिस्सा ढह गया जिसकी चपेट में परिसर से लगी छह दुकानें आ गईं। सुबह जब स्थानीय लोग और दुकानदार मौके पर पहुंचे तो मलबा देखकर हड़कंप मच गया। कई दुकानों के शटर, छज्जे और सामने का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिला। जानकारी के अनुसार, प्रभावित दुकानें पिछले करीब 20 वर्षों से संचालित हो रही थीं। इनमें विभिन्न प्रकार के व्यापार किए जाते थे। दुकानदारों ने बताया कि हादसे में उनका सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि हर वर्ष जर्जर भवनों की पहचान कर उन्हें हटाने या मरम्मत कराने की घोषणा की जाती है लेकिन धरातल पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। लोगों का कहना है कि यदि भवन का समय रहते तकनीकी निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत या ध्वस्तीकरण किया गया होता, तो इस तरह की घटना से बचा जा सकता था।

पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट एक घंटे तक रहा बंद

मऊगंज। जिले में मंगलवार को दलित-आदिवासी महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में आदिवासी महिला-पुरुषों ने पुनर्वास की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने झऊरा सहित अन्य गांवों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान घर टूटने के बाद अब तक जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया। इससे करीब एक घंटे तक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में उनके मकान तोड़ दिए, लेकिन बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवारों को छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि पिछले एक महीने से वे लगातार कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार आवेदन एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक भेज दिया जाता है और मामला पटवारी स्तर पर अटक जाता है। दलित-आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष बुद्धसेन साकेत ने बताया कि जिला प्रशासन ने पुनर्वास के लिए सात दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन 21 दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के पास न रहने के लिए मकान है और न ही भोजन की समुचित व्यवस्था।

गोवंश को बचाने के प्रयास में नहर में गिरा कोयला लदा ट्रेलर, चालक सुरक्षित

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के देवसर क्षेत्र में सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा टल गया, जब सड़क पर बैठे गोवंश को बचाने के प्रयास में कोयला लदा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित नहर में जा गिरा। घटना देवसर एसडीओपी कार्यालय के सामने पूर्वी बाईपास की है। राहत की बात यह रही कि हादसे में चालक सुरक्षित बच गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेलर क्रमांक MP 19 ZG 3436 सिंगरौली से कोयला लेकर सीधी की ओर जा रहा था। चालक लवकुश केवट, निवासी पड़रिया कला, ने बताया कि रात करीब एक बजे पूर्वी बाईपास मार्ग पर डिवाइडर के समीप सड़क अपेक्षाकृत संकरी होने के कारण अचानक सामने गोवंश आ गया। चालक ने वाहन को बचाने के उद्देश्य से ट्रेलर दूसरी ओर मोड़ दिया। इसी दौरान सामने से एक हाइवा वाहन आता दिखाई दिया। दोनों वाहनों की टक्कर से बचने के प्रयास में ट्रेलर सड़क किनारे नहर की ओर चला गया जहां किनारे की मिट्टी धंसने से वाहन संतुलन खो बैठा और नहर में उतर गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के कारण कुछ समय के लिए मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। समाजसेवी योगेश द्विवेदी ने कहा कि देवसर क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के पीछे सड़क का संकरा होना तथा मार्गों पर आवारा गोवंश का विचरण प्रमुख कारणों में शामिल हैं। उन्होंने संबंधित विभाग से राष्ट्रीय राजमार्ग का शीघ्र चौड़ीकरण, प्रभावी सड़क सुरक्षा उपाय और आवारा गोवंश के समुचित प्रबंधन की मांग की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार

जनसुनवाई में गूंजीं सड़क और घरेलू हिंसा की समस्याएं

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मंगलवार को जिला पंचायत में आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। इस दौरान ग्राम सलैया के करीब 20 ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्राम सरेठी की एक महिला ने पति द्वारा लगातार मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय और सख्त कार्रवाई की मांग की। दोनों मामलों में जिला प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्राम सलैया के निवासी सुधीश कुमार केवट के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव की लगभग एक हजार की आबादी आज भी पक्की सड़क सुविधा से वंचित है। गांव तक पहुंचने का मुख्य मार्ग कच्चा होने के कारण बारिश के मौसम में पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तथा किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सहित संबंधित विभागों में कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण की दिशा में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने से बरसात के दिनों में कीचड़ भरे रास्तों पर चलना मजबूरी बन जाता है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है। कई लोगों के पैरों में संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत कराने की मांग की। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि ग्रामीणों का ज्ञापन प्राप्त हो गया है। मामले की जांच कराई जाएगी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ग्रामीणों के लिए बेहतर आवागमन व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी जनसुनवाई में ग्राम सरेठी निवासी संजू जायसवाल ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति शराब के नशे में अक्सर उनके साथ मारपीट करते हैं तथा देर रात भोजन बनाने के लिए दबाव डालते हैं। विरोध करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की जाती है। पीड़िता ने प्रशासन से सुरक्षा, न्याय और आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। जनसुनवाई के दौरान प्रशासन ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश देने की बात कही। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि इस बार उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा।

निगाही मोड़ पर दो पक्षों में विवाद, युवक घायल; वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निगाही मोड़ पर मंगलवार को दो पक्षों के बीच विवाद का मामला सामने आया। घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही है। पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के पीछे कथित तौर पर आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि, विवाद के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तथ्यों का सत्यापन कर रही है। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने घायल युवक को मौके से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इसी बीच किसी राहगीर द्वारा मोबाइल फोन से बनाया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगा। वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम की भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

अंतरिक्ष में 'विक्रम-1'

संपादकीय

अंतरिक्ष में भारत के निजी क्षेत्र ने भी प्रवेश कर लिया है। 'विक्रम-1' और 'मिशन आगमन' ने सर्वप्रथम सफलता हासिल की है, जब एक निजी कंपनी के रॉकेट ने अंतरिक्ष तक सफल उड़ान भरी और पृथ्वी की निश्चित कक्षा में स्थापित किया। यह सफल प्रयोग और प्रक्षेपण 'स्काईरूट एयरोस्पेस' नामक निजी कंपनी ने किए हैं। यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक का रॉकेट था, जिसे पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचा कर इस कंपनी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इतिहास रचा है, अंतरिक्ष को एक बार फिर खंगाला है तथा अनुसंधान को वाकई एक नया आसमान दिया है। अभी तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण का काम 'इसरो' ही करता रहा था, जो एक सरकारी संस्थान है, लिहाजा उसे सरकार एक निश्चित बजट मुहैया कराती रही है। इसरो ने अंतरिक्ष में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन निजी क्षेत्र को अनुमति देना और फिर एक निजी कंपनी द्वारा रॉकेट भेजने के संकल्प को साकार करना वाकई अद्भुत, अप्रतिम, अनिर्वचनीय है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े रहे विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने या अन्य लक्ष्य प्राप्त करने का बाजार 60,000 से 90,000 करोड़ रुपए का है। जाहिर है कि अवसरों के आसमान खुले हैं और इस क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं भरपूर हैं। 'विक्रम-1' की ऐतिहासिक सफलता तब हासिल की गई है, जब करीब 120 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसरो से इस्तीफे दे दिए हैं अथवा वीआरएस ले लिया है। यह विदाई या अलगाव बेहद चिंताजनक माना गया, क्योंकि ये तकनीकी चेहरे भारत के 'चद्रयान-4' और 'गगनयान' जैसे विराट, दुस्साध्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े थे। वे सभी कार्यक्रम अपने अंतिम और निर्णायक चरण में हैं। इस्तीफा देने वाले कई इसरो वैज्ञानिक और इंजीनियर अंतरिक्ष संबंधी स्टार्टअप्स से जुड़ गए। 'विक्रम-1' भेजने वाली 'स्काईरूट एयरोस्पेस' कंपनी की स्थापना भी 2018 में पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका ने की थी, जिन्होंने इसरो की नौकरी छोड़ी थी और यह स्टार्टअप शुरू किया था। इसरो से कुछ चेहरे विदाई लेते हैं, तो उसे 'राष्ट्रीय क्षति' नहीं मानना चाहिए।

वे किसी स्टार्टअप अथवा निजी कंपनी से जुड़ना चाहें, तो इसरो को उन्हें एक निश्चित अवधि तक अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि वे अपनी पेशेवर क्षमताओं का विस्तार कर सकें और आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध हो सकें। 'विक्रम-1' परोक्ष रूप से इसरो का ही सृजन है, लिहाजा निजी क्षेत्र को भी 'राष्ट्रीय विस्तार' मानना चाहिए, क्योंकि अंतरिक्ष में, अंततः भारतीय 'तिरंगा' ही जाता है। यह डा. विक्रम साराभाई की ही विरासत है, जिन्होंने इसरो की स्थापना की और अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू किया। बहरहाल अब तो प्रधानमंत्री मोदी का 'वंदे मातरम्' लिखा कार्ड भी अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। हमारा सभी का अंतिम लक्ष्य 'भारत' ही है। निजी क्षेत्र की यह अंतरिक्ष-सफलता अमरीका और चीन के बाद भारत ने ही हासिल की है। कितना गर्व और गौरव महसूस होना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियो संदेश के जरिए 'मिशन आगमन' की टीम को बधाई दी है, राष्ट्र-निर्माण और आत्मनिर्भरता में उनकी भूमिका को सराहा है और प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात का न्यौता दिया है।

यह बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत है। भारत में भी अंतरिक्ष से जुड़ा एक बाजार खुलेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में कुछ पेलोड भेजे गए हैं। मसलन-इन ऑर्बिट रोबोटिक आर्म, भविष्य के मिशनों के लिए उपग्रह प्रणालियों का टेस्ट करेगा क्यूबसैट, नई अंतरिक्ष तकनीकों के सत्यापन के लिए टेस्ट सैटेलाइट, पिन पुलर एवं रिलीज नट सैटेलाइट छोड़ने के मैकेनिज्म के प्रभाव जांचेगा और 32 हीरों से बना कमल। भारत के दो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कुछ दिन बिता कर अध्ययन कर चुके हैं।

कैंसर की महंगी दवाएं— जीवन का अधिकार बनाम इलाज की कीमत

सौरभ वार्ष्णेय

कैंसर आज केवल एक गंभीर बीमारी नहीं, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चिकित्सा विज्ञान ने कैंसर के उपचार में उल्लेखनीय प्रगति की है और नई जीवनरक्षक दवाओं ने लाखों मरीजों को नई उम्मीद दी है। किंतु विडंबना यह है कि इन आधुनिक दवाओं की अत्यधिक कीमतें गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इलाज को लगभग असंभव बना देती हैं। ऐसे में प्रश्न केवल चिकित्सा का नहीं, बल्कि जीवन के संवैधानिक अधिकार का बन जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की महंगी दवाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब तलब करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने उस कैंसर मरीज की मृत्यु पर गहरी चिंता व्यक्त की, जो जीवनरक्षक दवाओं को किफायती बनाने से संबंधित मामले के निर्णय की प्रतीक्षा करते-करते दुनिया से विदा हो गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह केवल दवाओं की कीमत का विवाद नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को प्राप्त जीवन और गरिमा के अधिकार का प्रश्न है। यह टिप्पणी देश की स्वास्थ्य नीति के लिए एक गंभीर संदेश है कि न्याय में देरी कई बार जीवन की हानि का कारण बन जाती है। वास्तविकता यह है कि भारत में हर वर्ष लाखों लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं। आधुनिक लक्षित और इम्यूनोथेरेपी दवाओं की कीमत कई बार लाखों रुपये प्रति माह तक पहुंच जाती है। अधिकांश परिवार इतनी बड़ी राशि वहन करने में सक्षम नहीं होते। परिणामस्वरूप अनेक लोग अपनी वर्षों की जमा-पूंजी खर्च कर देते हैं, कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जमीन-जायदाद बेच देते हैं या फिर आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही इलाज छोड़ने को विवश हो जाते हैं। ऐसे अनेक मामलों में बीमारी से पहले आर्थिक संकट परिवार को तोड़ देता है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि नई दवाओं के अनुसंधान, परीक्षण और विकास में दवा कंपनियां अरबों रुपये का निवेश करती हैं। पेटेंट व्यवस्था उन्हें सीमित अवधि तक अपने आविष्कार का आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार देती है, जिससे भविष्य के अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए नवाचार और अनुसंधान की रक्षा आवश्यक है। किंतु जब जीवनरक्षक दवाएं आम नागरिक की पहुंच से बाहर हो जाएं, तब सरकार का दायित्व और भी बढ़ जाता है कि वह जनहित और व्यावसायिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करे। इस दिशा में सरकार को बहुआयामी कदम उठाने होंगे। आवश्यक कैंसर रोधी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाना, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना, सरकारी अस्पतालों में इन दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाना तथा जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक हित में पेटेंट कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों का विवेकपूर्ण उपयोग करना समय की मांग है। साथ ही, देश में दवा अनुसंधान और घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित कर आयात पर निर्भरता कम करना भी दीर्घकालिक समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक भी है। स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में समय पर निर्णय अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि यहां विलंब का अर्थ कई बार किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाना होता है। इसलिए ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है। एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राष्ट्र की पहचान केवल आर्थिक विकास से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और गंभीर बीमारी से जूझ रहे नागरिकों को कितना सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान कर पाता है। कैंसर की दवाएं कोई विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन बचाने का अनिवार्य साधन हैं। इसलिए सरकार, दवा उद्योग, चिकित्सा समुदाय और न्यायपालिका–सभी को मिलकर ऐसा संतुलित और मानवीय समाधान विकसित करना होगा, जिसमें अनुसंधान और नवाचार भी सुरक्षित रहें तथा कोई भी मरीज केवल आर्थिक अभाव के कारण जीवनरक्षक उपचार से वंचित न रह जाए।

संविधान और संप्रभु भारत का अमर प्रतीक तिरंगा

श्वेता गोयल

विश्व में प्रत्येक राष्ट्र का अपना-अपना राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज ही उसकी मर्यादा और अस्मिता से जुड़ा होता है लेकिन इस मायने में हमारा राष्ट्र ध्वज 'तिरंगा' अन्य राष्ट्र ध्वजों के मुकाबले अनेक विशेषताएं धारण किए हुए है। चूंकि अंग्रेजों से भारत की मिली आजादी के चंद दिन पहले ही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान भारतीय तिरंगे को देश के आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाया था, इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 22 जुलाई को 'राष्ट्रीय ध्वज दिवस' मनाया जाता है। आधिकारिक रूप में तिरंगे को अपनाने के बाद से यह देश की एकता, साहस, और आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। राष्ट्रीय ध्वज दिवस भारत की सम्प्रभु राष्ट्र बनने की यात्रा का स्मरण कराता है। तिरंगा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए इसके कठिन संघर्ष और एकजुट एवं समृद्ध राष्ट्र के लिए अपने लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। हमारा राष्ट्र ध्वज न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा, गौरव, शक्ति, आदर्श और आकांक्षाओं का प्रतीक है बल्कि समूचे विश्व को त्याग की भावना एवं शाति का संदेश भी देता है। यह हमारी स्वतंत्रता का भी प्रतीक है क्योंकि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को एकजुट करने में इसकी बहुत अहम भूमिका रही। तिरंगे ने ही भारतवासियों को एकता और भाईचारे का संदेश देकर उन्हें एक सूत्र में पिरोकर अंग्रेजों से लोहा लेने को प्रेरित किया था। तब क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान अपने प्राणों से भी बढ़कर होता था, इसीलिए अंग्रेजों की लाठियां व गोलियां खाते हुए भी उन्होंने इसे कभी झुकने नहीं दिया।

तीन रंगों की पट्टियों वाले राष्ट्रीय ध्वज की सबसे ऊपर की केसरिया रंग की पट्टी त्याग, बल और पौरूष की प्रतीक है जबकि बीच वाली सफेद पट्टी शांति और सत्य की प्रतीक है और सबसे नीचे की हरे रंग की पट्टी हरियाली, समृद्धि एवं सम्पन्नता की प्रतीक है। झंडे के बीचों-बीच सफेद पट्टी में स्थित गहरे नीले रंग का अशोक चक्र आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 24 तीलियों वाला अशोक चक्र देश की प्रगति, राष्ट्र के कानून और धर्म के पहिये का प्रतीक है। डा. सर्वपल्ली राधकृष्णन के शब्दों में कहें तो जो लोग इस ध्वज के नीचे कार्य करेंगे, उन्हें सत्य और सदाचार के सिद्धांतों का पालन करना होगा। राष्ट्र ध्वज के नीचे कार्य करने वालों से उनका तात्पर्य सरकारों और नौकरशाहों से था। राष्ट्र कोकिला सरोजिनी नायडू ने भी राष्ट्र ध्वज की महत्ता का उल्लेख करते हुए संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज का प्रस्ताव पेश करते समय 22 जुलाई 1947 को कहा था कि नए भारत के सभी नागरिकों को इस राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करना होगा और इसके नीचे कोई छोटा-बड़ा नहीं होगा।

राष्ट्र ध्वज का सफर 7 अगस्त 1906 को आरंभ हुआ था। हरे, पीले और लाल रंग की तीन पट्टियों से बना यह राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता के पारसी बागान में फहराया गया था। उस ध्वज पर ऊपर की हरी पट्टी पर एक ही पंक्ति में सफेद रंग के आठ कमल अंकित थे जबकि बीच वाली पीली पट्टी पर देवनागरी में गहरे नीले रंग से वंदेमातरम् लिखा था और नीचे की लाल पट्टी पर बायीं ओर एक सफेद सूर्य और दायीं ओर एक-एक सफेद चन्द्रमा और तारा अंकित थे। 'भारत का झंडा' नामक यह ध्वज हालांकि भारत के सभी धर्मों, सम्प्रदायों और साम्प्रदायिक सद्भावना को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया था लेकिन यह ध्वज सर्वमान्य नहीं हो पाया। 1917 में डा. एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 'होमरूल आन्दोलन' चलाया गया था। उस समय एक नया राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया, जिसमें लाल और हरे रंग की एक के बाद एक कुल 9 समानान्तर और तिरछी पट्टियां थी। उस ध्वज के बीचों-बीच 7 तारे थे और एक कोने में चांद व तारा अंकित थे जबकि उसके ऊपरी बायें कोने में 'यूनियन जैक' का चित्र (झंडे का चौथाई भाग) बनाया गया था। झंडे में यूनियन जैक के इस चित्र को सम्मिलित किए जाने के कारण ही यह अधिकांश लोगों द्वारा नापसंद कर दिया गया क्योंकि इस चित्र को राष्ट्रीय ध्वज में स्थान देने का अर्थ यही माना गया कि भारतीय समाज की ब्रिटिश सम्प्रभुत्ता के प्रति स्वीकृति है। तब एक ऐसे ध्वज की आवश्यकता महसूस की गई, जो प्रत्येक धर्म, सम्प्रदाय और विचारधाराओं के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के साथ देशवासियों के लिए जीवन-मरण का प्रतीक भी बन सके।

1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस के अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के पिंगली वैंकैया नामक क्रांतिकारी युवक ने महात्मा गांधी को एक ऐसा ध्वज भेंट किया, जिसमें लाल व हरे रंग की केवल दो पट्टियां थी लेकिन पंजाब के एक बुजुर्ग नेता रायजादा पंडित हंसराज ने गांधी जी को सुझाव दिया कि इस ध्वज में चरखे को भी अंकित किया जाए और तब गांधी जी ने यह सुझाव स्वीकारते हुए हिन्दुओं के लिए केसरिया रंग, मुस्लिमों के लिए हरा रंग तथा अन्य सम्प्रदायों के लिए ध्वज में सफेद रंग को भी शामिल किया। 31 दिसम्बर 1929 को रावी नदी के तट पर इसी तिरंगे को फहराते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। हालांकि बहुत से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज को जातियों व धर्म-सम्प्रदाय से जोड़ना उचित नहीं लगा, अतः 1931 में राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप के निर्धारण के लिए कराची कांग्रेस ने 7 व्यक्तियों की एक समिति बनाई और समिति ने एक ही रंग (केसरिया) के ध्वज में नीचे बायीं ओर लाल रंग के चरखे का चिन्ह अंकित करने का सुझाव दिया, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात् पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई और उस बैठक में तिरंगे ध्वज को ही बीच की सफेद पट्टी में चरखे सहित मान्यता प्रदान की गई और उस निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह रही कि तीनों पट्टियों के रंगों को धर्म-सम्प्रदायों से न जोड़कर उनके गुणों के आधार पर ही स्वीकार किया गया। इस ध्वज का आकार लम्बाई और चौड़ाई में 3:2 रखा गया। 1924 में आजादी के लिए संघर्षरत श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' ने झंडा गीत ''विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा'' की रचना की और महात्मा गांधी ने उस गीत के दूसरे और तीसरे भाग को हटाकर उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। वह गीत पहली बार कानपुर में 1925 में कांग्रेस सम्मेलन में सामूहिक रूप से गाया गया। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोष ने भी इसे एक लाख लोगों के साथ गाया और देखते ही देखते यह गीत क्रांतिकारियों का सबसे लोकप्रिय गीत बन गया। चाहे कांग्रेस का कोई सम्मेलन हो, कोई प्रभात फेरी हो अथवा क्रांतिकारियों का कोई आन्दोलन, ऐसे हर अवसर पर यही झंडा गीत बड़े ही जोशीले अंदाज में गाया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के चंद दिनों पहले जब भारत के सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक स्वरूप स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा चली तो 1931 में सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए ध्वज को ही पुनः राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया लेकिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक में पं. नेहरू ने चरखे के स्थान पर इसमें देश की प्रगति, राष्ट्र के कानून और धर्म के पहिये के प्रतीक 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को रखने का सुझाव दिया। संविधान सभा के सभी सदस्य इस सुझाव से सहमत हो गए और उसी दिन से राष्ट्रीय ध्वज को नए रूप में स्वीकार लिया गया। इस प्रकार हमारे राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए करीब 41 वर्षों का बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा।

वर्षा ऋतु में खान-पान और हमारा पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान

आचार्य ललित मुनि

हमारी परम्परा में जीवन पद्धति में भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ऋतु और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम माना गया है। हमारे ऋषि-मुनियों और आयुर्वेदाचार्यों ने हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर यह सिद्ध किया कि प्रत्येक ऋतु के अनुसार भोजन में परिवर्तन करना चाहिए। आयुर्वेद में इसे ऋतुचर्या कहा गया है। इसका उद्देश्य शरीर के दोषों का संतुलन बनाए रखना तथा ऋतु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों से रक्षा करना है। वर्षा ऋतु को आयुर्वेद में विशेष सावधानी का समय माना गया है। यह केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, बल्कि शरीर की पाचन क्षमता, वातावरण और रोगों की प्रकृति में भी बदलाव का काल है। यदि इस समय खान-पान में सावधानी न बरती जाए तो अनेक प्रकार के संक्रमण, पाचन संबंधी विकार और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं

वर्षा ऋतु में क्यों बदल जाता है शरीर का स्वभाव?ग्रीष्म ऋतु की तीव्र गर्मी के बाद जब वर्षा होती है, तब वातावरण में नमी बढ़ जाती है और सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार, इस समय जठराग्नि अर्थात पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है। भोजन पहले की अपेक्षा धीरे पचता है और शरीर रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यही कारण है कि वर्षा ऋतु में दस्त, उल्टी, टाइफाइड, हैजा, वायरल संक्रमण तथा त्वचा संबंधी रोगों की संभावना बढ़ जाती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि वर्षा के मौसम में बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद तेजी से पनपते हैं। दूषित जल और भोजन अनेक संक्रामक रोगों का कारण बनते हैं। इसलिए इस मौसम में केवल स्वाद नहीं, बल्कि भोजन की शुद्धता, ताजगी और पाचन क्षमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पूर्वजों की दूरदर्शिताआज की तरह पहले हर मौसम में हर प्रकार की सब्जियां उपलब्ध नहीं होती थीं। इसलिए हमारे पूर्वज वर्षा ऋतु आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेते थे। ग्रीष्म ऋतु में गेहूं, चावल, दाल, गुड़, घी और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ संग्रहित कर लिए जाते थे। इसी समय दाल की बड़ी, बिजौरी, पापड़, सूखी मिर्च, अमचूर, इमली तथा विभिन्न प्रकार के अचार तैयार किए जाते थे। अनेक क्षेत्रों में सब्जियों और पत्तेदार भाजियों को काटकर धूप में सुखाया जाता था। छत्तीसगढ़ में इन्हें सुखसी, सुखड़ी, सुखौंत, खोइला अथवा खेलरा जैसे नामों से जाना जाता है। मेथी, पालक, लाल भाजी, चौलाई और अन्य सागों को सुखाकर वर्षा ऋतु में उपयोग किया जाता था। मांसाहारी समुदाय भी मछली और मांस को सुखाकर सुरक्षित रखते थे ताकि वर्षा के दिनों में ताजा मांस पर निर्भर न रहना पड़े। यह केवल भोजन संग्रह की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि मौसम के अनुकूल जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति थी। वर्षा ऋतु में क्या खाना चाहिए?आयुर्वेद वर्षा ऋतु में हल्का, गर्म और ताजा भोजन करने की सलाह देता है। मूंग की दाल, पुराना चावल, गेहूं, जौ, सादा खिचड़ी, सूप तथा कम मसालों में बना हुआ भोजन आसानी से पचता है। भोजन में अदरक, काली मिर्च, जीरा, हींग, हल्दी और धनिया जैसे मसालों का सीमित उपयोग पाचन शक्ति को बढ़ाने में सहायक माना गया है। गुनगुना पानी पीना, उबला हुआ जल प्रयोग करना तथा भोजन ताजा बनाकर खाना इस ऋतु में विशेष लाभकारी माना गया है। गुड़, घी और सीमित मात्रा में देशी मसालों का प्रयोग शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा पाचन को भी सहयोग देता है। किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए?भारतीय परंपरा में वर्षा ऋतु के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन सीमित रखने की सलाह दी गई है। इसका कारण यह है कि इस मौसम में उनमें कीट, अंडे, फफूंद और रोगाणुओं की संभावना बढ़ जाती है। आज भी चिकित्सक बिना अच्छी तरह धोए और पकाए पत्तेदार सब्जियां खाने से बचने की सलाह देते हैं। गैर-मौसमी सब्जियां और बदलती आदतेंकृषि तकनीक और संरक्षित खेती के कारण आज लगभग हर मौसम में हर प्रकार की सब्जियां उपलब्ध हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक वस्तु हर ऋतु में शरीर के लिए समान रूप से लाभकारी भी हो। अनेक गैर-मौसमी सब्जियां रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और कृत्रिम तकनीकों की सहायता से तैयार की जाती हैं। आज वर्षा ऋतु में टमाटर, प्याज या अन्य सब्जियों के महंगे होने पर व्यापक चर्चा होती है। जबकि प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या वास्तव में इस मौसम में उनका अधिक सेवन आवश्यक है? हमारे पूर्वजों ने जिस वस्तु का प्राकृतिक उत्पादन जिस ऋतु में होता था, उसी समय उसका सेवन अधिक किया। इससे शरीर भी प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखता था। पारंपरिक भोजन की वैज्ञानिकताभारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के लिए अलग-अलग भोजन विकसित हुए। कहीं बड़ी और पापड़ का उपयोग होता था, कहीं सूखी सब्जियां बनाई जाती थीं। मसालों का चयन भी मौसम के अनुसार किया जाता था। हींग, मेथी, अदरक और काली मिर्च जैसे पदार्थ केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पाचन सुधारने के लिए उपयोग किए जाते थे। वर्षा ऋतु में भोजन कम मात्रा में और समय पर करने की परंपरा भी थी। सूर्यास्त के बाद देर रात भोजन करने की आदत नहीं थी। आयुर्वेद के अनुसार देर रात भोजन करने से जठराग्नि कमजोर होती है और अपच, अम्लता तथा मोटापे जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। आयुर्वेद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है; 'ऋतुभुक्, हितभुक्, मितभुक्। 'अर्थात् ऋतु के अनुसार भोजन करें, अपने शरीर के लिए हितकारी भोजन करें और संयमित मात्रा में भोजन करें। यदि केवल इस एक सूत्र का पालन कर लिया जाए तो अनेक रोगों से बचा जा सकता है। प्रकृति के साथ चलना ही स्वास्थ्य का मार्गआज जीवनशैली बदल गई है। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन, फास्ट फूड और हर मौसम में हर प्रकार का भोजन करने की आदत सामान्य हो गई है। परिणामस्वरूप मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग और पाचन संबंधी विकार तेजी से बढ़ रहे हैं। यह केवल चिकित्सा का विषय नहीं, बल्कि हमारी भोजन संस्कृति से जुड़ा प्रश्न भी है। वर्षा ऋतु हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देती है। यदि हम इस मौसम में हल्का, ताजा और सुपाच्य भोजन करें, दूषित एवं गैर-मौसमी खाद्य पदार्थों से बचें, समय पर भोजन करें तथा आयुर्वेद की ऋतुचर्या का पालन करें, तो अनेक बीमारियों से स्वाभाविक रूप से बच सकते हैं।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से नई हरित क्रांति की शुरुआत

भारत ने रेल परिवहन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन इस तकनीक का उपयोग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन बताते हुए कहा कि इसे भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और भारतीय कंपनी ने ही विकसित किया है। यह उपलब्धि केवल रेलवे की सफलता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की दिशा में देश की बड़ी छलांग है।

कांतिलाल मांडोत

जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली यह ट्रेन 89 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 14 स्टेशनों के बीच संचालित होगी। दस कोच वाली इस ट्रेन में आठ यात्री कोच और दो पावर कार हैं। इसमें 682 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है जबकि कुल लगभग 2600 यात्री यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि इसका डिजाइन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के अनुसार तैयार किया गया है। यह पूरी दूरी लगभग दो घंटे में तय करेगी और यात्रियों के लिए किराया मात्र 5 से 25 रुपये रखा गया है ताकि आम लोग भी इस आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सकें। इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इंजन है। ट्रेन में लगभग 440 किलोग्राम हाइड्रोजन संग्रहित की जा सकती है और एक बार ईंधन भरने के बाद यह करीब 356 किलोमीटर तक चल सकती है। अनुमान है कि प्रतिदिन दो फेरे लगाने में लगभग 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत होगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन का संचालन पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इंजन से धुएं की जगह केवल जलवाष्प यानी भाप और थोड़ा पानी निकलता है। इस कारण इसे शून्य उत्सर्जन वाली तकनीक माना जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के साथ हरियाणा देश में ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। जींद रेलवे स्टेशन के पास देश का पहला हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और रीफ्यूलिंग प्लांट तैयार किया गया है। यहां इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक के माध्यम से पानी से प्रतिदिन लगभग 430 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। स्टेशन परिसर में लगभग 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन सुरक्षित रखने की क्षमता विकसित की गई है। इस परियोजना पर लगभग 112 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ट्रेन का डिजाइन और एकीकरण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया जबकि हाइड्रोजन प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने में मेधा सर्वो ड्राइव्स तथा ग्रीनएच इलेक्ट्रोलिसिस जैसी भारतीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि फिलहाल यह ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर के मार्ग पर चलेगी लेकिन भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लागत कम करने और तकनीक को अधिक सक्षम बनाने के लिए लगातार अनुसंधान करेगी। उनके अनुसार यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है जिसकी क्षमता लगभग 3200 हॉर्सपावर है और यह परिचालन दूरी के लिहाज से भी दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन सेवाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इस परियोजना से जींद और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऊर्जा सुरक्षा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत पर उसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि पेट्रोल, डीजल और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रेलवे का बड़ा हिस्सा डीजल इंजनों पर निर्भर था, लेकिन पिछले बारह वर्षों में लगभग 99 प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया गया है। इससे डीजल पर निर्भरता काफी कम हुई है और अब हाइड्रोजन जैसी नई तकनीक ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा को 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इनमें कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, भिवानी का पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज, नारनौल का महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल, दिल्ली अमृतसर कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग का हरियाणा खंड, अंबाला काला अंब राष्ट्रीय राजमार्ग, जींद गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग, कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास तथा हांसी बरवाला राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने जींद में चलाए गए स्वच्छता अभियान की भी सराहना की और लोगों से इसे जन आंदोलन बनाए रखने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर को हरियाणा के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन राज्य के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परियोजना नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। हाइड्रोजन ट्रेन के लोको पायलट राजेश कुमार ने बताया कि यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली, कम शोर वाली और पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है। इसमें लगे फ्यूल सेल में एक ओर से हाइड्रोजन और दूसरी ओर से ऑक्सीजन पहुंचती है। रासायनिक प्रक्रिया के दौरान बिजली उत्पन्न होती है जिससे ट्रेन चलती है जबकि उपउत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प और पानी निकलता है। इस कारण यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाइड्रोजन आखिर बनती कैसे है, यह भी समझना आवश्यक है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जब बिजली की सहायता से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से पानी को अलग किया जाता है तब हाइड्रोजन प्राप्त होती है। यदि इस प्रक्रिया में सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोजन स्वयं ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि ऊर्जा को संग्रहित करने और आवश्यकता के समय उपयोग करने का प्रभावी माध्यम है। अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा को हाइड्रोजन के रूप में संग्रहित कर बाद में फ्यूल सेल के जरिए बिजली में बदला जा सकता है। हाइड्रोजन तकनीक के अनेक फायदे हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग समाप्त हो जाता है और केवल भाप निकलती है, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। यह जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाती है और आयातित पेट्रोलियम पर खर्च कम करने में मदद करती है। जिन क्षेत्रों में ओवरहेड बिजली लाइन बिछाना कठिन है वहां हाइड्रोजन ट्रेन बेहतर विकल्प बन सकती है। इसका संचालन अपेक्षाकृत शांत होता है जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से इसकी लागत घटेगी और रेलवे के साथ अन्य परिवहन क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बढ़ेगा। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत सबसे पहले जर्मनी में हुई थी जहां 2018 में पहली यात्री ट्रेन चली और 2022 से नियमित वाणिज्यिक सेवा शुरू हुई। फ्रांस में कई क्षेत्रीय परियोजनाएं चल रही हैं। चीन ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित की है जबकि स्वीडन अभी परीक्षण चरण में है। भारतीय रेलवे का दावा है कि ब्रॉड गेज पर चलने वाली क्षमता के मामले में भारत की हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली ट्रेनों में शामिल है।

सरकार की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के अंतर्गत भविष्य में देश के ऐतिहासिक और पहाड़ी मार्गों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना है। जहां विद्युतीकरण कठिन या महंगा है वहां यह तकनीक विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है।

एमसीबी में समय-सीमा बैठक: कलेक्टर ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के दिए सख्त निर्देश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में जिले के सभी विभागों के कार्यों, विकास योजनाओं, लंबित प्रकरणों और जनहित से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे और सभी लंबित शिकायतों एवं प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अंकिता सोम, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार, सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

आरटीआई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और सुशासन तिहार के आवेदनों की समीक्षा: कलेक्टर ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) पोर्टल की समीक्षा करते हुए जिन विभागों के अधिकारी अब तक पोर्टल पर ऑनबोर्ड नहीं हुए हैं उन्हें तत्काल प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि आरटीआई से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त मांग एवं शिकायत संबंधी लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिका और सभी नगर पंचायतों को लंबित आवेदनों का सर्वे कर प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और पीजी पोर्टल में दर्ज शिकायतों के समय पर समाधान पर भी जोर दिया गया कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी अधिकारी को किसी प्रकरण के निराकरण में कठिनाई आती है तो वह तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए।

राजस्व प्रकरणों के जल्द निपटारे पर जोर: बैठक में राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान विवादित खाता विभाजन, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन और त्रुटि सुधार जैसे लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए कलेक्टर ने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, खड़गवां और भरतपुर तहसीलों में कुल 2,687 राजस्व प्रकरण लंबित हैं उन्होंने नियमित सुनवाई कर इन मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। वृक्ष कटाई से जुड़े लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।

आंगनबाड़ी, कृषि और पीएम स्वनिधि पर विशेष फोकस: कलेक्टर ने विद्युत विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने, चांटी आंगनबाड़ी केंद्र का शीघ्र हैंडओवर कराने, रामगढ़ में आंगनबाड़ी भवन निर्माण तथा कृषि विद्यालय के लिए भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को अधिक से अधिक सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने तथा वितरित ऋण की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ई-श्रम पोर्टल की समीक्षा के दौरान खाद्य एवं श्रम विभाग को समन्वय बनाकर अप्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा: ैठक में आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की गई लोक निर्माण विभाग को मंच एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करने, जबकि पीएमजीएसवाई, जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूर्व निर्धारित दायित्वों के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति पर नजर: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन, पेयजल आपूर्ति, हैंडपंप मरम्मत, क्लोरीनेशन, वाटर एटीएम की नियमित जांच तथा प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए वहीं क्रेडा विभाग को जल जीवन मिशन के तहत सोलर संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने को कहा गया।

दूरस्थ गांव के किसान ने अपनाई आधुनिक खेती: खरीफ सीजन में पहली बार करेंगे नैनो डीएपी का उपयोग

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। एमसीबी जिले में किसान अब आधुनिक कृषि तकनीकों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर स्थित विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम सिंगरौली निवासी किसान शिवलाल ने खरीफ सीजन 2026 में पहली बार अपनी धान की फसल में नैनो डीएपी उर्वरक का उपयोग करने का निर्णय लिया है उनका मानना है कि वैज्ञानिक खेती और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है शिवलाल ने बताया कि अब तक वे पारंपरिक डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते थे, लेकिन इस वर्ष प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति और कृषि विभाग से नैनो डीएपी की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने इसे अपनाने का फैसला किया आसपास के किसानों से मिले सकारात्मक अनुभवों ने भी उन्हें नई तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष गांव के कई किसानों ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग किया था इन किसानों की फसल में बेहतर बढ़वार और संतोषजनक उत्पादन देखने को मिला इसी सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने भी इस बार अपनी धान की खेती में नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है। शिवलाल के अनुसार नैनो डीएपी का सबसे बड़ा लाभ इसका आसान उपयोग है पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोरियों की तुलना में इसकी छोटी बोतलों को खेत तक ले जाना बेहद सुविधाजनक होता है इससे परिवहन में आसानी होती है समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा कम मात्रा में उपयोग होने के कारण इसका प्रबंधन भी सरल हो जाता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि नैनो डीएपी पौधों तक आवश्यक पोषक तत्व अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाने में मदद करता है इसके संतुलित उपयोग से फसल की बढ़वार बेहतर होती है, उर्वरकों की बर्बादी कम होती है और खेती की लागत में भी कमी आती है खरीफ सीजन में किसानों को नैनो उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से इनकी पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 : पांचवें दिन 1300 से ज्यादा कार्यक्रम, 9 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा नशामुक्ति का संदेश

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष जनजागरूकता अभियान 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0 ' को पांचवें दिन भी व्यापक जनसमर्थन मिला। 15 से 30 जुलाई तक संचालित इस अभियान के तहत सोमवार को प्रदेशभर में 1300 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके माध्यम से 9 लाख से अधिक नागरिकों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाया गया अभियान के दौरान पुलिस ने केवल जागरूकता तक सीमित न रहते हुए युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, ग्रामीणों, वाहन चालकों, श्रमिकों और खिलाड़ियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया तथा स्वस्थ और नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया प्रदेशभर में रैलियां, मैराथन, वाहन रैलियां, जनसंवाद, ग्राम चौपाल, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रथ, पोस्टर-पंपलेट वितरण, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, चित्रकला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं सहित सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्कूल-कॉलेजों, छात्रावासों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाट-बाजार, औद्योगिक क्षेत्रों, झुग्गी बस्तियों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर नशे से होने वाले स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी कई स्थानों पर नागरिकों और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। अभियान को उस समय और मजबूती मिली जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भोपाल देहात स्थित ऐतिहासिक जगदीशपुर (चमन महल) में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान का समर्थन करते हुए नशामुक्त मध्यप्रदेश का संकल्प लिया मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर प्रदेशवासियों से भी नशे से दूर रहने की अपील की प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी अभियान के तहत विशेष गतिविधियां आयोजित की गईं अलीराजपुर में निमाड़ी बोली के गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया जबकि खंडवा में 28 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर करीब 1.20 लाख लोगों तक संदेश पहुंचाया गया ग्वालियर में ऑटो और ई-रिक्शा पर नशामुक्ति संदेश वाले पोस्टर लगाए गए वहीं बालाघाट, मंडला, खरगोन और उज्जैन में रैली, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया अभियान, शपथ कार्यक्रम और पुनर्वास केंद्रों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया।

शिवपुरी दुष्कर्म मामले में नया मोड़ आरोपी के पिता ने निष्पक्ष जांच की मांग, पुलिस बोली- शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार बालिग है आरोपी

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म प्रकरण में मंगलवार को नया मोड़ आ गया आरोपी के पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की उनका आरोप है कि पारिवारिक रंजिश के चलते उनके बेटे को झूठे मामले में फंसाया गया है वहीं पुलिस का कहना है कि उपलब्ध शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार आरोपी बालिग है और मामले की जांच सभी तथ्यों के आधार पर जारी है आरोपी के पिता अपने समर्थकों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और आवेदन सौंपा उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2026 को उनके पुत्र के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था उनका कहना है कि शिकायतकर्ता महिला और उसके मायके पक्ष से पुराना विवाद चल रहा है जिसके कारण उनके बेटे के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है पिता ने दावा किया कि घटना के समय उनका बेटा घटनास्थल पर नहीं था बल्कि किसी अन्य स्थान पर मौजूद था उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से की जा सकती है उन्होंने पुलिस से मांग की कि मामले की जांच केवल आरोपों के आधार पर नहीं बल्कि डीएनए परीक्षण, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष रूप से की जाए आवेदन के साथ उन्होंने कथित सीसीटीवी फुटेज की पेन ड्राइव भी पुलिस को सौंपी है। आरोपी के पिता का यह भी कहना है कि उनका बेटा नाबालिग है और वर्तमान में पोहरी उप जेल में बंद है उन्होंने मांग की कि यदि वह नाबालिग है तो उसे तत्काल किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किशोर बंदी गृह में स्थानांतरित किया जाए ताकि उसकी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े वहीं बैराड़ थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की शैक्षणिक अंकसूची और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की है जिनके अनुसार वह बालिग है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की शिकायत और उपलब्ध प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है आरोपी पक्ष द्वारा प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी गौरतलब है कि बैराड़ थाना क्षेत्र की 19 वर्षीय विवाहिता ने 14 जुलाई को विशाल रावत के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया था। महिला का आरोप है कि आरोपी पिछले दो वर्षों से शादी का दबाव बना रहा था उसने 24 मार्च 2026 को घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल किया और विवाह के बाद भी उसे परेशान करता रहा। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि 12 जुलाई को मायके आने के दौरान आरोपी ने रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की और दोबारा दुष्कर्म किया पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है।

शिवपुरी के सरकारी स्कूलों की खुली पोल, 33 छात्र दर्ज, लेकिन एक भी नहीं पहुंचा; मध्यान्ह भोजन भी नहीं बना

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले की सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति मंगलवार को हुए औचक निरीक्षण में सामने आ गई कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर बैराड़ तहसीलदार द्रगपाल सिंह बैश ने पोहरी विकासखंड के सड़ और ककरई गांव स्थित शासकीय विद्यालयों का निरीक्षण किया इस दौरान सड़ प्राथमिक विद्यालय में 33 छात्र नामांकित होने के बावजूद एक भी छात्र उपस्थित नहीं मिला इतना ही नहीं स्कूल में मध्यान्ह भोजन भी तैयार नहीं किया गया था जिस पर तहसीलदार ने नाराजगी जताते हुए शिक्षक को फटकार लगाई निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय सड़ में केवल एक शिक्षक मौजूद मिले विद्यालय में छात्रों की पूरी तरह अनुपस्थिति और मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन में लापरवाही देखकर तहसीलदार ने इसे गंभीर मामला माना उन्होंने उपस्थित शिक्षक से अनुपस्थिति के कारणों की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से संपर्क किया जाए तथा स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावी ढंग से संचालित हों साथ ही मध्यान्ह भोजन योजना का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर अर्पित वर्मा द्वारा जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और उचित मूल्य की राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश के तहत की गई । इसी क्रम में मंगलवार सुबह करीब 11 से 11:30 बजे के बीच तहसीलदार द्रगपाल सिंह बैश ने दोनों विद्यालयों का निरीक्षण किया इसके बाद तहसीलदार ने ग्राम ककरई स्थित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया।

शिवपुरी की अशोक विहार कॉलोनी मे मगरमच्छ का आतंक: पानी भरे प्लॉट में डेरा

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र स्थित अशोक विहार कॉलोनी में मगरमच्छ की मौजूदगी से रहवासियों में दहशत का माहौल है कॉलोनी में दो मोबाइल टावरों के पास स्थित पानी से भरे एक खाली प्लॉट को मगरमच्छ ने अपना ठिकाना बना लिया है स्थानीय लोगों का कहना है कि वह पिछले कई महीनों से यहां देखा जा रहा है और अब उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ने लगी हैं रहवासियों के अनुसार मगरमच्छ अक्सर रात के समय पानी से निकलकर कॉलोनी की सड़कों पर आ जाता है। कई लोगों ने उसे सड़क पार करते हुए भी देखा है इस कारण शाम ढलने के बाद लोगों ने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया है और कॉलोनी में भय का माहौल बना हुआ है स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सबसे अधिक खतरा स्कूल जाने वाले बच्चों, सुबह-शाम टहलने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों को है लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते मगरमच्छ का रेस्क्यू नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है कॉलोनीवासियों ने बताया कि उन्होंने पिछले कई महीनों में वन विभाग को कई बार मगरमच्छ की मौजूदगी और उसकी गतिविधियों की जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनका आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद विभाग ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

पेपर लीक के विरोध में शिवपुरी में आंदोलन की तैयारी, छात्राओं ने मांगी धरना-रैली की अनुमति, सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे कथित पेपर लीक मामलों के विरोध में शिवपुरी में छात्रों और युवाओं ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है मंगलवार को छात्रा सोम्या और श्रुति जैन ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा और शांतिपूर्ण धरना एवं रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी छात्राओं का कहना है कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है इसलिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। छात्राओं ने बताया कि देशभर में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर युवाओं में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी इस विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है लेकिन वे उसमें शामिल नहीं हो सकीं ऐसे में उन्होंने शिवपुरी में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया है। आवेदन में उन्होंने 21 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक शहर के पोलो ग्राउंड, माधव चौक पर शांतिपूर्ण धरना आयोजित करने की अनुमति मांगी है इसके साथ ही शहर में जागरूकता रैली निकालने की भी मांग की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुद्दे से जुड़ सकें और युवाओं की चिंता को समझ सकें छात्राओं का कहना है कि पेपर लीक की घटनाओं से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का मनोबल टूटता है और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके और युवाओं का भरोसा बहाल हो। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित धरना और रैली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(ख) के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार के अनुरूप होगी।

पिपरिया में डेंगू-मलेरिया रोकथाम को लेकर प्रशासन सख्त : एसडीएम ने दिए जलभराव रोकने के निर्देश, स्कूलों में जागरूकता अभियान तेज करने पर जोर

मीडिया ऑडीटर, पिपरिया (निप्र)। मानसून के दौरान मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं 'डेंगू निरोधक माह' के तहत मंगलवार को पिपरिया जनपद सभाकक्ष में एसडीएम आकिफ खान की अध्यक्षता में मलेरिया विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपने कार्यालयों और आसपास के क्षेत्रों में जलभराव रोकने, नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए गए साथ ही शिक्षा विभाग से स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाने और विद्यार्थियों को डेंगू एवं मलेरिया से बचाव के उपायों की जानकारी देने को कहा गया बैठक में एसडीएम आकिफ खान ने कहा कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी विभागों और आम नागरिकों की सहभागिता से ही इन पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय परिसरों, शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी पानी जमा न होने दिया जाए जहां जलभराव की संभावना हो वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों से कहा कि विद्यालयों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों को मच्छरजनित रोगों के कारण, लक्षण और बचाव के उपायों की जानकारी दी जाए ताकि वे स्वयं भी सतर्क रहें और अपने परिवारों को भी जागरूक कर सकें उन्होंने कहा कि बच्चों के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी संदेश घर-घर तक पहुंचाया जा सकता है बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए आमजन को विस्तृत जानकारी दी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि मच्छरों के काटने से फैलने वाली इन बीमारियों के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, कमजोरी और ठंड लगना शामिल हो सकते हैं ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के दौरान बुखार से पीड़ित लोगों की मलेरिया जांच भी की गई स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि समय पर जांच और उपचार से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया गया जिसमें मलेरिया निरीक्षक आर.के. पटेल और अन्य अधिकारियों ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपायों की जानकारी दी बैठक में लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई बनाए रखने की विशेष सलाह दी गई। अधिकारियों ने कहा कि बेकार पड़े टायर, टूटे बर्तन, गमले, नारियल के खोल, पानी की टंकियां तथा अन्य ऐसे स्थान जहां पानी जमा हो सकता है उन्हें नियमित रूप से खाली और साफ रखा जाए। उन्होंने बताया कि ठहरे हुए पानी में मच्छर तेजी से अंडे देते हैं जिससे डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

स्वच्छ पेयजल की दिशा में पहल,अक्तवार और घघरा के सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने विकासखंड भरतपुर के ग्राम अक्तवार और घघरा में सार्वजनिक हैंडपंपों का क्लोरीनेशन अभियान चलाया। अभियान के तहत सभी सार्वजनिक हैंडपंपों में निर्धारित मानकों के अनुसार क्लोरीन का उपयोग कर पेयजल को सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया पूरी की गई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निर्देश तथा सहायक अभियंता जयंत कुमार चंदेल के मार्गदर्शन में विभाग की तकनीकी टीम और हैंडपंप टेक्निशियनों ने प्रत्येक हैंडपंप में 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग किया। इससे पेयजल में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी तथा जलजनित बीमारियों की रोकथाम सुनिश्चित होगी। अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के उपयोग, जल स्रोतों की नियमित साफ-सफाई, जल गुणवत्ता बनाए रखने और जल संरक्षण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया ।

पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के साथ मारपीट, पत्थर फेंके, तमीज से बात करने को लेकर विवाद, शिकायत के बाद परिजनों ने मांगी माफी

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम के पैलेस रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर सोमवार रात पेट्रोल भराने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक अपने साथियों के साथ वापस पहुंच गया और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान पंप पर पथराव भी किया गया। मारपीट और हंगामे की पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से मामला शांत हो गया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

पेट्रोल भराने के दौरान हुआ था विवाद: घटना सोमवार रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति पेट्रोल भराने के लिए नायरा पेट्रोल पंप पर आया था। इस दौरान पेट्रोल कर्मचारी भीमसिंह से तमीज से बात करने को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने समझाइश देकर विवाद शांत करा दिया और संबंधित व्यक्ति वहां से चला गया।

कुछ देर बाद साथियों के साथ पहुंचा युवक: बताया जा रहा है कि विवाद के कुछ समय बाद वही व्यक्ति अपने साथ तीन-चार लोगों को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। उसके साथ आए लोगों में से एक व्यक्ति के हाथ में प्लास्टिक का पाइप था। वह सीधे कर्मचारी के पास पहुंचा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

बीच बचाव करने पर बढ़ा हंगामा: मारपीट होते देख पास खड़े दूसरे कर्मचारी ने बीच बचाव करने की कोशिश की। लेकिन हमलावर नहीं माने तो अन्य कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गहमागहमी की स्थिति बन गई। बचाव के दौरान कर्मचारियों को भी लट्ठ उठाना पड़ा। कुछ देर के लिए पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा हो गई।

● पथराव भी किया गया

मारपीट के दौरान पेट्रोल पंप पर पत्थर भी फेंके गए। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना का वीडियो रात करीब 11:30 बजे सामने आया, जिसके बाद मामला चर्चा में आया।

● पुलिस पहुंची, दोनों पक्ष थाने पहुंचे

घटना की सूचना मिलने पर माणकचौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों की तलाश कर उन्हें थाने लाया। इसके बाद पेट्रोल पंप संचालक संजित मेहता और कर्मचारी भी थाने पहुंचे कार्रवाई के लिए आवेदन दिया।

● परिजनों ने मांगी माफी:

थाने में दोनों पक्षों की बातचीत के दौरान मारपीट करने वाले व्यक्ति के परिवार के लोग भी पहुंचे। उन्होंने संबंधित व्यक्ति की ओर से पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारियों से माफी मांगी। बताया गया कि संबंधित व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। इसके बाद पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारियों ने आपसी सहमति से उसे माफ कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया।

● मिस कयुनिकेशन के कारण हुआ विवाद

माणकचौक थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मिस कम्युनिकेशन के कारण विवाद हुआ था। बाद में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता हो गया।

बच्चों को स्कूल भेजा, 38 वर्षीय महिला ने फांसी लगाई, देवास में मंदिर से लौटकर उठाया कदम, दरवाजा तोड़ने पर पति ने देखा शव

मीडिया ऑडीटर, देवास (निप्र)। देवास शहर के शुक्रवारिया हाट क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक 38 वर्षीय महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला की पहचान रिंकी पति मनोज पडियार (38) के रूप में हुई है। घटना के दिन सुबह उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल के लिए ऑटो में बैठाया था। उस समय उनके पति मनोज सुबह की सैर पर गए हुए थे। पार्षद बाली घोषी ने बताया कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रिंकी पूजा करने मंदिर गई और फिर घर लौट आई। कुछ देर बाद जब पति मनोज पडियार घर पहुंचे, तो उन्होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आशंका होने पर मनोज ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो रिंकी फंदे पर लटकी हुई थीं। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि, आत्महत्या के स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आए हैं और पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। पार्षद घोषी भी घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि महिला ने बच्चों को स्कूल भेजने और मंदिर जाने के बाद फांसी लगाई। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा ने बताया कि सूचना पर टीम मौके पर पहुंची थी। शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है।

बाइक पर चढ़ा जहरीला सांप, चालक की जान बची, बारिश में बिलों से बाहर निकल रहे सांप, विशेषज्ञों ने वाहन जांचने और सतर्क रहने की दी सलाह

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर शहर के व्यस्त जवाहर रोड स्थित अंजनी ट्रांसपोर्ट के सामने मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे खड़ी एक बाइक पर अचानक जहरीला सांप चढ़ गया। बाइक चालक जैसे ही वाहन के पास पहुंचा, उसकी नजर सांप पर पड़ गई। चालक ने बिना घबराए तुरंत खुद को बाइक से दूर कर लिया, जिससे संभावित बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और काफी देर तक क्षेत्र में दहशत का माहौल बना रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांप बाइक के अलग-अलग हिस्सों में घूमता रहा, जिससे कोई भी वाहन के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आसपास मौजूद लोगों ने सावधानी बरतते हुए काफी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित तरीके से बाइक से हटाया। इसके बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली और यातायात सामान्य हो सका।

बारिश में बढ़ा सर्पदंश का खतरा: बारिश का मौसम शुरू होते ही जिले में सांप और अन्य जहरीले जीव-जंतु अपने बिलों तथा छिपे हुए स्थानों से बाहर निकलने लगे हैं। लगातार हो रही बारिश और जलभराव के कारण ये जीव सुरक्षित जगहों की तलाश में घरों, दुकानों, वाहनों और आबादी वाले इलाकों तक पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिले में सर्पदंश के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में दोपहिया और चारपहिया वाहनों में सांपों के छिपने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वाहन लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़ा रहने पर इंजन, सीट या अन्य हिस्सों में सांप शरण ले सकते हैं।

विशेषज्ञों ने बरतने को कहा विशेष सावधानी: वन्यजीव और सर्प विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान वाहन स्टार्ट करने या चलाने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करें। खासकर लंबे समय से खड़े वाहनों के आसपास सतर्कता बरतें। घरों, दुकानों और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई बनाए रखें, ताकि सांप और अन्य जहरीले जीवों के छिपने की संभावना कम हो। विशेषज्ञों ने यह भी सलाह दी है कि यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या मारने का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित सर्प विशेषज्ञ को सूचना दें, ताकि सुरक्षित तरीके से उसका रेस्क्यू किया जा सके। साथ ही, सर्पदंश की स्थिति में झाड़-फूंक के बजाय तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय उपचार कराना ही सबसे सुरक्षित उपाय है।

मन्दसौर में महिला को सांप ने डसा: पति मरे हुए सांप को थैली में लेकर अस्पताल पहुंचा, डॉक्टरों ने एंटी वेनम देकर भर्ती किया

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर के फतेहगढ़ गांव में सोमवार देर रात एक महिला को घर में घुसे सांप ने डस लिया। महिला की चीख सुनकर पहुंचे पति ने पहले सांप को मार दिया। इसके बाद उसे प्लास्टिक की थैली में रखकर घायल पत्नी के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने महिला का प्राथमिक उपचार कर एंटी वेनम लगाया और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। फिलहाल महिला डॉक्टरों की निगरानी में है। जानकारी के अनुसार, फतेहगढ़ निवासी किरण धाकड़ (30), पति बलदेव धाकड़ सोमवार रात अपने कच्चे मकान में फर्श पर बिछे बिस्तर पर पांच वर्षीय बेटी के साथ सो रही थीं। इसी दौरान देर रात एक सांप ने उनके हाथ पर काट लिया। सांप के काटते ही उनकी नींद खुल गई। पहले उन्हें लगा कि किसी नुकीली चीज ने चुभन की है, लेकिन कुछ देर बाद दर्द बढ़ने लगा।

पति सांप को मारकर थैली में रखकर अस्पताल लाया: किरण ने कमरे की लाइट जलाकर देखा तो सामने सांप दिखाई दिया। उन्होंने दूसरे कमरे में सो रहे पति बलदेव धाकड़ को आवाज लगाई। बलदेव मौके पर पहुंचे और लकड़ी से सांप को मार दिया। इसके बाद उन्होंने मरे हुए सांप को प्लास्टिक की थैली में रखा और पत्नी को लेकर तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला का तत्काल इलाज शुरू किया। प्राथमिक उपचार के साथ एंटी वेनम लगाया गया। इसके बाद किरण धाकड़ को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सांप की लंबाई करीब डेढ़ फीट थी। बाद में मरे हुए सांप को सुरक्षित स्थान पर फेंक दिया गया। परिजनों के अनुसार, उनका मकान कच्चा है और घर के आसपास जंगल क्षेत्र है। आशंका है कि इसी वजह से सांप घर में घुस आया। घटना के समय किरण की पांच वर्षीय बेटी भी उनके पास सो रही थी।

नर्मदापुरम में सुबह से हो रही बारिश

सोहागपुर-बनखेड़ी में डेढ़-डेढ़ इंच पानी गिरा, 3 दिन अच्छी बारिश की संभावना

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में मंगलवार की शुरुआत बारिश के साथ हुई। तड़के 5 बजे से रिमझिम बारिश जारी है। जो सुबह 11बजे तक भी जारी रही। इसके बाद बारिश की बौछारें होती रही। पिछले 12 घंटे में अबतक में 20 मिमी यानि पौन इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा सोहागपुर, बनखेड़ी, इटारसी, पिपरिया, डोलरिया में भी बारिश हो रही है। यसोहागपुर, बनखेड़ी में डेढ़-डेढ़ इंच पानी दर्ज हुआ है। बारिश होने से सुबह से वातावरण ठंडा हो गया। बारिश की राह देख रहे किसानों के चेहरे खिल उठे। अब अगले तीन दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसमविद पीके रैकवार ने बताया कि इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। लोकल सिस्टम बनने से बारिश होने का अनुमान है।

धान रोपाई का काम तेज हुआ: बारिश के बाद किसानों ने खेतों में धान की रोपाई का काम तेज कर दिया। एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण धान और सोयाबीन की फसल प्रभावित हो रही थी। इससे बोवनी का काम रुका था।

पिछले साल से 14 इंच बारिश: जिले में 1 जून से अब तक जिले में महज 9.50 इंच ही बारिश हुई, जो सामान्य से काफी कम है। पिछले साल 1 जून से 21 जुलाई के दौरान 24 इंच बारिश हो चुकी थी। इस साल सीजन की बारिश 14 इंच कम दर्ज हुई।

रायसेन में रात एक बजे से हो रही तेज बारिश

7 घंटे गिरे पानी से सूखे धान के खेत लबालब, किसानों को राहत मिली

रायसेनमीडिया ऑडीटर, (निप्र)। रायसेन में लंबे इंतजार के बाद सोमवार-मंगलवार की रात करीब 1 बजे शुरू हुई तेज बारिश सुबह तक लगातार जारी रही। करीब सात घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने जिले की तस्वीर बदल दी। सूखे पड़े धान के खेत पानी से लबालब हो गए, नदियों और तालाबों में पानी भर गया, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक झरने भी बहने लगे। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा।

लगातार बारिश के चलते भोपाल रोड सहित कई स्थानों पर एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया। आसपास की नदियों का पानी खेतों तक पहुंच गया और लंबे समय से सूखे पड़े खेतों में फिर से जान लौट आई। सदलतपुर घाटी सहित आसपास के पहाड़ों से प्राकृतिक झरने बहने लगे, जिन्हें देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

करीब 15 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल मुरझाने लगी थी और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बीच हुई इस बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी।

बारिश के बाद किसानों ने फिर से धान की रोपाई शुरू कर दी। उनका कहना है कि यह बारिश फसल के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं है। जिन खेतों में पानी की कमी के कारण खेती प्रभावित हो रही थी, वे अब पूरी तरह पानी से भर चुके हैं। किसानों को उम्मीद है कि समय पर हुई यह बारिश इस बार अच्छी पैदावार का आधार बनेगी।

स्कॉर्पियो से 1.1 किलो अफीम जब्त, हरियाणा के तस्कर गिरफ्तार, बोनट में छिपाकर ले जा रहे थे माल

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर जिले की नारायणगढ़ थाना पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी स्कॉर्पियो से 1 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है। पुलिस ने वाहन में सवार हरियाणा निवासी दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के कब्जे से अफीम के साथ करीब 20 लाख रुपए कीमत की स्कॉर्पियो और दो एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ में अफीम सप्लाई करने वाले एक आरोपी का नाम सामने आया है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश के साथ पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है।

बांसखेड़ी फंटा पर चेकिंग में पकड़ी गई स्कॉर्पियो: पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एसपी विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में सोमवार देर शाम नारायणगढ़ थाना पुलिस बादरी-बूढ़ा रोड स्थित बांसखेड़ी फंटा पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो (HR29AT7468) को रोककर उसकी तलाशी ली। जांच के दौरान पुलिस को वाहन के बोनट के अंदर एक विशेष जगह पर छिपाकर रखी गई अवैध अफीम मिली।

बोनट में छिपाकर रखी थी 1.100 किलो अफीम: पुलिस ने जब्त अफीम का वजन कराया तो वह 1 किलो 100 ग्राम निकली। पुलिस के अनुसार, बरामद अफीम की अनुमानित कीमत करीब 1.65 लाख रुपए है। इसके बाद पुलिस ने वाहन में मौजूद दोनों लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखविंदर (26) पिता मेनपाल जाट निवासी ग्राम बाढ़ड़ा, जिला चरखी दादरी और आशीष (22) पिता राजकुमार जाट निवासी ग्राम लाड, तहसील बाढ़ड़ा, जिला चरखी दादरी हरियाणा के रूप में हुई है।

पूछताछ में सामने आया अफीम सप्लायर का नाम: प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे यह अफीम मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के लिलदा निवासी मुकेश से लेकर आए थे। पुलिस ने मुकेश को भी मामले में आरोपी बनाया है। वह फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।

थाना प्रभारी राजेंद्र पवार ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में अफीम के स्रोत की जानकारी मिली है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि अफीम की डिलीवरी किसे दी जानी थी और इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस ने 21 लाख से ज्यादा का माल किया जब्त: नारायणगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.100 किलो अफीम के अलावा करीब 20 लाख रुपए कीमत की स्कॉर्पियो कार और 29 हजार रुपए कीमत के दो एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं। मामले में थाना नारायणगढ़ पर अपराध क्रमांक 229/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 और 29 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।

लग्जरी गाड़ियां बन रही हैं तस्करी का नया जरिया: मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अब तस्कर लग्जरी वाहनों का इस्तेमाल करने लगे हैं।

रात में बरसा फिर थमा, सुबह से रिमझिम बारिश जारी, खंडवा में लंबी खेंच के बाद एक इंच पानी गिरा; खेती के लिए मिला बूस्टर डोज

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा में सोमवार रात को दो घंटे तक रूक-रूककर बारिश हुई। इस दौरान एक इंच तक पानी रिकॉर्ड किया गया। वहीं मंगलवार सुबह से बादल छाए रहे, दोपहर तक रिमझिम बरसात जारी रही। बारिश ने जहां गर्मी और उमस को शांत कर दिया। वहीं खेती के लिए एक वरदान साबित हो गई। धूप और पानी ना मिलने से मुरझा रही फसलों को बूस्टर डोज मिल गया।

बारिश का पिछले साल जैसा ही हाल: मौसम के पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो इस साल की स्थिति पिछले साल जैसी ही बनी हुई है 2025 जुलाई में कुल 136 मिमी बारिश हुई थी। तब 9 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का एक लंबा ड्राई स्पेल आया था, जिसमें 14 जुलाई को महज 2 मिमी की मामूली बूंदाबांदी हुई थी। इस साल जुलाई के पहले सप्ताह में तो बहुत अच्छी बारिश हो गई, लेकिन उसके बाद 8 जुलाई से मौसम खुला था।

आगे क्या...अभी अगले 5 दिन ऐसे ही रहेगा मौसम: मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून के इस तरह कमजोर पड़ने और लंबे ड्राई स्पेल आने के पीछे मुख्य कारण अलनीनो का प्रभाव है। लगातार हो रही जंगलों की कटाई और पर्यावरण में आ रहे बदलावों की वजह से भी मानसूनी सिस्टम को आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है।

मकान का ताला तोड़कर सामान फैलाया, गुल्लक के रुपए निकाले

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाना के ऋद्धि-सिद्धि एवेन्यू कॉलोनी में रविवार देर रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे, पूरे घर का सामान अस्त-व्यस्त कर दिया और गुल्लक तोड़कर उसमें रखे करीब 4 से 5 हजार रुपए चोरी कर ले गए।

वारदात के बाद तीनों बदमाश कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। फुटेज में वे चड्डी-बनियान पहने, नंगे पैर और हाथों में पत्थर लिए घूमते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

रात में सूने मकान को बनाया निशाना: कॉलोनी निवासी देवेंद्र डोडियार

के घर में हुई। देवेंद्र कॉलेज छात्र हैं और इस मकान में रहकर पढ़ाई करते हैं, जबकि उनका परिवार शहर के दूसरे घर में रहता है। रविवार को वह परिवार के साथ शहर से बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया।

सुबह लौटे तो टूटा मिला ताला: सोमवार सुबह करीब 5 बजे जब देवेंद्र घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था। बदमाश घर में रखी गुल्लक तोड़कर उसमें जमा करीब 4 से 5 हजार रुपए नकद लेकर फरार हो चुके थे।

CCTV में कैद हुए तीन बदमाश: घटना की जानकारी मिलने के बाद कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में तीन संदिग्ध बदमाश चड्डी-बनियान पहने, नंगे पैर और हाथों में पत्थर लिए कॉलोनी में घूमते दिखाई दे रहे हैं। एक बदमाश घरों के बाहर झांकते हुए भी कैमरे में कैद हुआ है। वारदात का वीडियो अब सामने आया है।

रात के सन्नाटे में बदमाशों का कॉलोनी में बेखौफ घूमना पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नियमित गश्त होती तो संभवतः चोरी की घटना टाली जा सकती थी।

पुलिस ने शुरू की जांच: चोरी की सूचना औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने और उनकी तलाश में जुटी है।

विश्व चैंपियन स्पेन फीफा रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा

नई दिल्ली ,एजेसीं। फीफा वर्ल्ड कप के विजेता स्पेन ने फिर से टॉप स्थान हासिल कर लिया है, जो इस साल की शुरुआत में उनके पास था। 'ला रोजा' ने रनर-अप अर्जेंटीना को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप मेन्स टीम का स्थान ले लिया। टूर्नामेंट के को-होस्ट मैक्सिको ने मार्च 2022 के बाद पहली बार टॉप 10 में वापसी की, जबकि क्वार्टर-फाइनलिस्ट नॉर्वे ने सबसे बड़ी बढ़त हासिल की। एक यादगार और ऐतिहासिक फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन हुआ जिसमें स्पेन (पहला स्थान, 1 पायदान ऊपर) ने अपना दूसरा प्रतिष्ठित खिताब जीता और विश्व रैंकिंग में टॉप स्थान फिर से हासिल किया। 'ला रोजा', जिसने अप्रैल में टॉप स्थान गंवा दिया था, ने अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी और 2026 संस्करण के रनर-अप अर्जेंटीना (दूसरा स्थान, 1 पायदान नीचे) पर भी काफी बढ़त बना ली। 2022 के चैंपियन ने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में हुए फाइनल में एक्स्ट्रा-टाइम में 1-0 से हारने के बाद अपना ताज और नंबर एक स्थान गंवा दिया। हालिया रैंकिंग अवधि में 105 मैच खेले जाने के बाद टॉप 10 में काफी बदलाव हुए हैं, जिनमें से 104 मैच हालिया ग्लोबल टूर्नामेंट में खेले गए थे। ब्राजील (पांचवां स्थान, 1 पायदान ऊपर) और मोरक्को (छठा स्थान, 1 पायदान ऊपर) दोनों ने पुर्तगाल (सातवां स्थान, 2 पायदान नीचे) को पीछे छोड़ दिया, जो राउंड ऑफ 16 में टूर्नामेंट जीतने वाली टीम से हारकर बाहर हो गया था। क्वार्टर-फाइनलिस्ट बेल्जियम (आठवां स्थान, 1 पायदान ऊपर) अपने पड़ोसी नीदरलैंड्स (नौवां स्थान, 1 पायदान नीचे) से आगे निकल गया, जबकि को-होस्ट मैक्सिको (दसवां स्थान, 4 पायदान ऊपर) ने जर्मनी (12वां स्थान, 2 पायदान नीचे) की जगह लेते हुए मार्च 2022 के बाद पहली बार टॉप दस में वापसी की। रैंकिंग में यह ताजा अपडेट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नतीजों को दिखाता है, जिसमें टॉप 90 टीमों में ज्यादातर बदलाव टूर्नामेंट की 48 टीमों के प्रदर्शन के सीधे नतीजे के तौर पर हुए हैं। उत्तरी अमेरिकी धरती पर धूम मचाने वाली दो अन्य टीमें सबसे ज़्यादा बढ़त हासिल करने वाली टीमों में शामिल हैं। स्विट्जरलैंड (15वें स्थान पर, 5 स्थान ऊपर) ने क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 5 स्थान की बढ़त हासिल की है, नॉर्वे (19वें स्थान पर, 12 स्थान ऊपर) ने भी ऐसा ही कमाल दिखाया है। स्कैंडिनेवियाई देशों ने न केवल रैंकिंग के इस नए संस्करण में सबसे बड़ी छलांग लगाई है, बल्कि अगस्त 2011 के बाद से अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति (तब वे 12वें स्थान पर थे) में भी पहुँच गए हैं।

विश्व कप जीतने पर स्पेन के खिलाड़ियों की चांदी

हर प्लेयर को मिलेगा 8.63 लाख डॉलर का बोनस

मैड्रिड,एजेसीं। स्पेन में सोमवार को देश की दूसरी वर्ल्ड कप जीत के बाद जश्न जारी रहा, रविवार को अर्जेंटीना के खिलाफ फेरान टोरेस के अतिरिक्त समय में किए गए गोल ने उन्हें एंड्रेस इनिएस्ता के साथ जगह दिलाई, जिन्होंने 2010 के फाइनल में अहम गोल किया था। नेशनल टीम की शर्ट में दूसरा स्टार जोड़ने के सम्मान के अलावा, स्पैनिश फुटबॉल फेडरेशन और टीम के 26 खिलाड़ियों के पास जश्न मनाने के बड़े फाइनेंशियल कारण भी हैं। 2026 वर्ल्ड कप जीतने पर स्पेन को फीफा से 5 करोड़ डॉलर की प्राइज मनी मिली, जबकि फेडरेशन को बढ़ी हुई स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू से भी फायदा होगा। स्पैनिश नेशनल टीम को ट्रैवल, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, स्पोर्ट्सवियर, एनर्जी, फूड और बेवरेज जैसे सेक्टर की 35 कंपनियों का सपोर्ट है। स्पेन का वर्ल्ड चैंपियन बनने से उसके टेलीविजन राइट्स की वैल्यू भी बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पूरे देश में रेप्लिका शर्ट की बिक्री पहले ही बढ़ गई है। टीम की ऑफ-व्हाइट अवे शर्ट अब स्पेन में लगभग बिक चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इस जीत का मतलब खिलाड़ियों के लिए अच्छी-खासी रकम भी है जिनमें से हर एक को वर्ल्ड कप विनर मेडल और रिंग के अलावा 756,000 यूरो (लगभग 863,000 डॉलर) का बोनस मिलेगा।

एफआईएच हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप में हरमनप्रीत भारत की कप्तानी करेंगे

नई दिल्ली ,एजेसीं। हॉकी इंडिया ने सोमवार को बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले एफआईएच वर्ल्ड कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की। इस टीम की कप्तानी हरमनप्रीत सिंह करेंगे। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और शानदार युवा प्रतिभाओं का मेल है। गोलकीपिंग विभाग में मोहित एचएस और सूरज करकेरा शामिल हैं, जबकि डिफेंस यूनिट में जरमनप्रीत सिंह, कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच शामिल हैं। मिडफील्ड की कमान मनप्रीत, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद की तिकड़ी संभालेगी, साथ ही नीलाकांता शर्मा और होनहार युवा खिलाड़ी राजिंदर सिंह और आदित्य अर्जुन लालागे भी इसमें शामिल होंगे। अटैक की जिम्मेदारी मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा के कंधों पर होगी। मुख्य कोच क्रेग फुल्टन को भरोसा है कि चुनी गई टीम के पास भारतीय हॉकी के इतिहास में अपना अध्याय लिखने का शानदार मौका है।

फुल्टन ने आगे कहा

'दबाव बनाना, जवाबी हमला करना और अच्छा प्रदर्शन करना सिर्फ हमारी रणनीतिक पहचान नहीं है। यह वह तरीका है जिससे यह ग्रुप हर दिन एक साथ ट्रेनिंग करता है और सोचता है। हम बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं। हम एक बार में एक ही मैच पर पूरा ध्यान देने की मानसिकता के साथ उतर रहे हैं।' फुल्टन ने कहा, '1975 (वर्ल्ड कप जीत) के बाद से 50 साल हो गए हैं। इस टीम के पास भारतीय हॉकी के इतिहास में अपना एक नया अध्याय लिखने का मौका है। हम इसे लेकर वाकई बहुत उत्साहित हैं। इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में शामिल भारत अपने सभी पूल-स्टेज मैच एमस्टेलवीन, नीदरलैंड में खेलेगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा, इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करेगा।

हर्डल को देश में जैवलिन जैसी लोकप्रियता दिलाना चाहता हूं: तेजस शिर्से

नई दिल्ली ,एजेसीं। 23 साल के तेजस शिर्से 110-मीटर हर्डल्स (बाधा दौड़) में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। उनका अगला लक्ष्य कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में देश के लिए पदक जीतना है। उन्होंने कहा कि वह देश में हर्डल को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले आईएएनएस से खास बातचीत में तेजस शिर्से ने कहा, 'जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। मैं वहां जाकर यह नहीं कहना चाहता कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रक्रिया मेरे लिए है। दुनिया के लिए जीत ही मायने रखती है। मुझे बस जीत की परवाह है। दुनिया भी जीत की ही परवाह करेगी। मैं दुनिया में सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। मैं जिस भी इवेंट में हिस्सा लूं, उसमें सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। अगर मेरी सोच ऐसी नहीं होगी, तो मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं बस कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में जाकर जीतना चाहता हूं—यही एकमात्र लक्ष्य है।'

कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में जगह बनाना तेजस शिर्से के लिए आसान नहीं रहा है। पिछले साल हर्डल के दौरान एक टक्कर के कारण उनके टखने में कई जगह चोट लग गई। उस वजह से उनका टखना तीन-चार जगहों से लगभग टूट गया था। उसके बाद, तेजस बहुत उदास हो गए थे।

उन्होंने कहा, 'सब कुछ सही करने के बावजूद, और बिना कुछ गलत किए भी, मेरे साथ ऐसा हो गया। मेरी रिकवरी रिलायंस फाउंडेशन की स्पोर्ट्स साइंस टीम की देखरेख में एक बेहतरीन सामूहिक प्रयास में हुई। इस टीम में कोच जेम्स हिलियर, फिजियोथेरेपिस्ट नीलेश मकवाना और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच क्षितिज भोइते शामिल थे। शुरुआत में उनका लक्ष्य मुझे बिना दर्द के दौड़ाना था। कॉमनवेल्थ गेम्स एक अव्यावहारिक लक्ष्य लग रहा था, लेकिन मैंने कोशिश करने का फैसला किया।'

शिर्से ने कहा, 'मैंने अप्रैल के बीच में ट्रेनिंग शुरू की और क्वालीफिकेशन मई के आखिर और जून की शुरुआत में होना था। इतने कम समय में क्वालीफाई करना और समय कम करना व्यावहारिक नहीं था। मेरे मन में यह बात थी कि अगर ऐसा हो जाता है, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में पदक जीतना लक्ष्य: तैराक साजन प्रकाश

नई दिल्ली ,एजेसीं। पेरिस ओलंपिक के बाद थकान और तनाव की वजह से ब्रेक लेने वाले अनुभवी भारतीय तैराक साजन प्रकाश प्रतियोगी तैराकी में वापसी कर रहे हैं। प्रकाश का कहना है कि उनका लक्ष्य ग्लासगो में शुरू हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स और सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों में पदक जीतना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बातचीत में आईएएनएस के सवाल का जवाब देते हुए प्रकाश ने कहा, 'मैं यह कहना चाहूंगा कि जब एथलीट बहुत कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करने, खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने और भारत का नाम रोशन करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, तो वे दर्द सहने के आदी हो जाते हैं और कई बातें समझ नहीं पाते। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, तो उन्हें समझ नहीं आता कि रिकवरी क्या है। रिकवरी और आराम भी ट्रेनिंग का ही हिस्सा हैं।' उन्होंने कहा, 'रिकवरी का मतलब हमेशा जोर लगाना नहीं होता। जब मैंने ब्रेक लिया, तो मुझे समझ आया कि मेरा शरीर बहुत बड़े शॉक में था और मुझे रिकवर करने और आराम करने की जरूरत थी। कभी-कभी जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आप आगे बढ़ते हैं, आराम बहुत जरूरी हो जाता है, यह रिकवरी का एक अहम हिस्सा है। यह भी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। इसलिए इससे मुझे वापसी करने में मदद मिली क्योंकि मैं सिर्फ स्विमिंग के बारे में सोचता हूं और प्रतियोगी तैराकी में ही अपनी अंदरूनी ताकत पाता हूं। मुझे बस ऐसा लगा कि अभी कई काम अधूरे हैं। मैं हमेशा से कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में पोडियम तक पहुंचना चाहता था, और मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता हूं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। मुझे लगता है कि ऐसा करके मैं अपने सपने पूरे कर लूंगा।

वन-डे कप में हैम्पशायर के लिए खेलेंगे आशुतोष शर्मा

नई दिल्ली,एजेसीं। पुरुषों के मेट्रो बैंक वन-डे कप के लिए हैम्पशायर ने ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा को साइन किया है। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। 27 वर्षीय आशुतोष इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) की तरफ से खेलते हैं, जिसके सह-मालिक हैम्पशायर के मालिक जीएमआर हैं। हैम्पशायर के क्रिकेट डायरेक्टर जाइल्स व्हाइट ने कहा, 'हम वन-डे कप के लिए आशुतोष को साइन करके बहुत खुश हैं। वह बहुत क्षमतावान खिलाड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें पता है कि ऊंचे स्तर पर कैसा प्रदर्शन करना होता है। हम उन्हें टीम में शामिल करने और हैम्पशायर की जर्सी में खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि हम इस प्रतियोगिता में पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं।' 27 वर्षीय बैटिंग ऑलराउंडर ने आईपीएल में अब तक कुल 3 सीजन खेले हैं। साल 2024 में आशुतोष ने पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए 11 मुकाबलों की 9 पारियों में 27 की औसत के साथ 189 रन बनाए। इस दौरान एक अर्धशतक भी लगाया। अगले दो सीजन आशुतोष ने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेला। इसके बाद आईपीएल 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 3.80 करोड़ रुपये में साइन किया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपने पहले सीजन में आशुतोष ने 13 मुकाबलों की 9 पारियों में 29.14 की औसत के साथ 204 रन बनाए।

आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ:

शुभमन गिल-मोसाद्देक हुसैन को पछाड़कर नाथन स्मिथ ने जीता जून माह का खिताब

नई दिल्ली,एजेसीं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज नाथन स्मिथ 'जून 2026' के लिए 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' चुने गए हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। कीवी खिलाड़ी ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल और बांग्लादेशी ऑलराउंडर मोसाद्देक हुसैन जैसे दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है। 27 वर्षीय स्मिथ ने इंग्लैंड में खेली गई 3 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 23 की औसत से सर्वाधिक 16 विकेट चटकाए थे। न्यूजीलैंड के कई मुख्य तेज गेंदबाजों के चोट के कारण बाहर होने के बाद स्मिथ ने जिम्मेदारी संभालते हुए दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। नाथन स्मिथ ने सोमवार को 'आईसीसी' के एक बयान में कहा, 'यह वाकई बहुत खास है। टीम के लिए इंग्लैंड का दौरा शानदार रहा और यह बहुत अच्छी बात है। मैं आमतौर पर व्यक्तिगत अवॉर्ड के लिए नहीं खेलता, लेकिन यह पहचान मिलना अच्छा लगता है और इससे भी जरूरी बात यह है कि मैंने सीरीज जीतने में योगदान दिया। व्यक्तिगत रूप से, जीत में योगदान देना बहुत संतोषजनक रहा। न्यूजीलैंड के लिए मैं बस यही करना चाहता हूं- पूरी कोशिश करना और जिस भी तरह से हो सके, योगदान देना। दुर्भाग्य से, सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, इसलिए मुझे आगे आकर नई गेंद से बॉलिंग की शुरुआत करनी पड़ी। मैंने घरेलू क्रिकेट में और पहले न्यूजीलैंड के लिए भी ऐसा किया है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना और नई गेंद से कुछ ओवर फेंकना अच्छा लगा।' नाथन स्मिथ का सबसे शानदार प्रदर्शन लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रहा, जहां उन्होंने दूसरी पारी में 70 रन देकर 6 विकेट लिए और मेजबान टीम की कमर तोड़ दी। उन्होंने इस यादगार मैच में कुल नौ विकेट लिए थे। दूसरे मैच में स्मिथ ने 1 विकेट निकालने के अलावा, 38 रन की पारी भी खेली।

● वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद लियोनेल मेसी ने दर्द

बोले-दर्द गहरा है, इस घाव को भरने में समय लगेगा

नई दिल्ली ,एजेसीं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के खिताबी मुकाबले में स्पेन से 1-0 से अर्जेंटीना की हार को लेकर लियोनेल मेसी ने दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार से उबरने में अर्जेंटीना की टीम को सिर्फ वक्त ही मदद करेगा। इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लियोनेल मेसी खिताब जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फेरान टोरेस के एक्स्ट्रा-टाइम गोल ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फेरान टोरेस के गोल ने स्पेन की जीत में अहम भूमिका निभाई, जिससे अर्जेंटीना खिताबी मुकाबले में हार गई। 39 वर्षीय मेसी के 2030 में होने वाले अगले वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीद नहीं है, हालांकि उन्होंने अभी तक संन्यास लेने की कोई योजना घोषित नहीं की है। मेसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दर्द बहुत गहरा है और इस घाव को भरने में समय लगेगा। लेकिन मैं उन सभी अच्छी यादों को भी संजोकर रखूंगा।' उन्होंने आगे लिखा, 'वे मैच जिन्हें हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर पलटा, वे पल जो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे और पूरे देश का समर्थन, जिसने इस ग्रुप की कड़ी मेहनत और कोशिशों के साथ मिलकर हमें एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन टीमों में शामिल किया।' अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज आसानी से पार किया और फिर फाइनल में पहुंचने के लिए अपने अगले चार नॉकआउट मैचों में देर से किए गए गोलों के दम पर जीत हासिल की। मेसी ने टूर्नामेंट का समापन आठ गोल और चार असिस्ट के साथ किया और कुछ लोगों का मानना ??था कि टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 'गोल्डन बॉल' अवॉर्ड न जीत पाना उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा।बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व स्टार खिलाड़ी ने अपने साथियों की तारीफ की और टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताया। उन्होंने कहा, 'अभी हमारी उपलब्धि की पूरी तरह से सराहना करना मुश्किल है, लेकिन यह ग्रुप लगातार दो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा।' 'हर शुभकामना और संदेश के लिए दिल से धन्यवाद। एक बार फिर, हम एक देश के तौर पर एकजुट हुए और साथ खड़े रहे, अर्जेंटीना होने का गर्व महसूस किया। मैं चैंपियनशिप जीतने पर स्पेन को भी बधाई देना चाहता हूं।'

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा टीम का इम्तिहान

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा टीम का इम्तिहान भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 23 जुलाई से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शुरू होने जा रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा भारतीय टीम इस दौरे पर उतरेगी, जहां कई नए खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा। वहीं, सिकंदर रजा की अगुआई में जिम्बाब्वे घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर भारत को कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगा।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में युवा टीम पर नजरें

इंग्लैंड दौरे के बाद भारत अब जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा। इस दौरे के लिए बीसीसीआई ने युवा खिलाड़ियों से सजी टीम चुनी है, जिसकी कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है। यह सीरीज भविष्य की टी20 टीम तैयार करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है।

टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, रवि बिश्नोई की एंट्री

सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम में एक अहम बदलाव किया गया। हैमस्ट्रिंग चोट के कारण वरुण चक्रवर्ती पूरे दौरे से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं। बीसीसीआई ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि उन्हें आराम दिया गया है या चयन नहीं हुआ।

अमरपाटन में भीम आर्मी का प्रदर्शन: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा धांधली की जांच की मांग, अंबेडकर प्रतिमा सौंदर्यीकरण को लेकर आंदोलन की चेतावनी

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले के अमरपाटन में मंगलवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारी दिल्ली में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरे और केंद्र एवं राज्य सरकार से कई मांगें रखीं कार्यकर्ताओं ने रामनगर रोड से सतना चौराहा तक जुलूस निकाला इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने अमरपाटन तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से उच्च न्यायालय के नाम ज्ञापन सौंपा।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग: प्रदर्शनकारियों ने देश में होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने मध्यप्रदेश के चर्चित व्यापमं मामले और शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल सके कार्यकर्ताओं ने मांग की कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाए और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

डॉ. अंबेडकर प्रतिमा परिसर के सौंदर्यीकरण की मांग: प्रदर्शन के दौरान अमरपाटन स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा परिसर के सौंदर्यीकरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रतिमा स्थल के विकास और सौंदर्यीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही है लेकिन अब तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थल का शीघ्र सौंदर्यीकरण कराया जाए और वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

6 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी: भीम आर्मी ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी 6 अगस्त से डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं उन्होंने कहा कि युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक मुद्दों को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रही तैनात: प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया था जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी गई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

रामपुर बघेलान जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 83 आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। आमजन की समस्याओं के समाधान और प्रशासन को जनता के करीब पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को रामपुर बघेलान तहसील कार्यालय में अनुभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने क्षेत्र से पहुंचे 83 आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे कलेक्टर ने प्रत्येक आवेदक से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जनसुनवाई में सबसे अधिक आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित प्राप्त हुए इनमें नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, भूमि संबंधी विवाद और अन्य राजस्व प्रकरणों से जुड़ी समस्याएं शामिल थीं कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि जनसुनवाई शासन और जनता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने स्तर पर सक्रियता से कार्य करें और लोगों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें जनसुनवाई के दौरान एसडीएम रामपुर बघेलान सुभाष मिश्रा, तहसीलदार रामपुर रमेश कोल, तहसीलदार कोटर आशुतोष मिश्रा, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

मानव सेवा की मिसाल : अमर ज्योति परिवार की प्रेरणा से श्यामनगर उचेहरा में 5 लोगों ने लिया देहदान का संकल्प

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मानव सेवा और समाज कल्याण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल करते हुए सतना के अमर ज्योति परिवार की प्रेरणा से श्यामनगर उचेहरा में पांच लोगों ने मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया यह आयोजन जिला कुशवाहा संघ, ब्लॉक उचेहरा एवं ब्लॉक इकाई उचेहरा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पूजा-अर्चना कर किया गया इस दौरान उपस्थित लोगों ने देहदान जैसे मानवीय कार्य को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसे चिकित्सा शिक्षा और मानव कल्याण के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान बताया। अमर ज्योति परिवार के संयोजक मनोहर डिगवानी ने कहा कि देहदान का संकल्प लेने वाले लोगों ने समाज के सामने सेवा और संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद भी मानव शरीर चिकित्सा शिक्षा और शोध कार्यों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है जिससे आने वाली पीढ़ियों के चिकित्सकों को सीखने का अवसर मिलता है और समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है उन्होंने कहा कि देहदान को महादान माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन समाप्त होने के बाद भी मानवता की सेवा करने का माध्यम बनता है उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से इस पुनीत अभियान से जुड़ने की अपील की कार्यक्रम में अमर ज्योति परिवार के संयोजक मनोहर डिगवानी सहित कमल पुरस्वानी, सुधीर जैन, दिलीप सोनी, रूपचंद छुट्टानी, अजय कुमार कुशवाहा, मीडिया प्रभारी एडवोकेट सुंदरलाल कुशवाहा, रामप्रताप कुशवाहा लाला, स्वामीदीन कुशवाहा, गौरीशंकर कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा, इंजीनियर नारायण कुशवाहा, अशोक कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे इस अवसर पर जिला कुशवाहा संघ के पदाधिकारी, आजीवन सदस्य, संरक्षक सदस्य, चंद्रगुप्त सेना, महिला मोर्चा सतना एवं मैहर जिले के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया उपस्थित लोगों ने देहदान के महत्व को समाज तक पहुंचाने और अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प लिया अमर ज्योति परिवार और कुशवाहा संघ की यह पहल समाज में मानवता, सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दे रही है।

इन पांच लोगों ने लिया देहदान का संकल्प:

1. रामलेख कुशवाहा।
2. जगतकिशोर कुशवाहा।
3. कालीचरण कुशवाहा
4. शकुंतला कुशवाहा
5. रामखेलावन कुशवाहा।

पेपर लीक पर कार्रवाई की मांग को लेकर गरीब सेना ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उठाई मांग

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर गरीब सेना के पदाधिकारियों ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में गरीब सेना ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। संगठन का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है गरीब सेना के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र-छात्राओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है संगठन ने आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे लोगों के साथ पुलिस कार्रवाई की जा रही है जिसकी उन्होंने निंदा की। संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रपति से मांग की कि देश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं विद्यार्थियों के विश्वास को कमजोर करती हैं और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं। गरीब सेना ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि केंद्र सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस नीति बनाई जाए साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सतना में पदोन्नति सूची में मृत सब इंस्पेक्टर का नाम, रिकॉर्ड सत्यापन पर उठे सवाल

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी कार्यवाहक उप निरीक्षकों की पदोन्नति सूची में मंगलवार को बड़ी लापरवाही सामने आई है सूची में एक ऐसे पुलिसकर्मी का नाम शामिल कर दिया गया जिनका निधन पिछले वर्ष हो चुका है इस मामले के बाद विभागीय रिकॉर्ड सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं जानकारी के अनुसार प्रदेशभर के 2035 कार्यवाहक उप निरीक्षकों की पदोन्नति सूची जारी की गई थी इसमें क्रमांक 1115 पर राकेश सिंह बघेल का नाम दर्ज है राकेश सिंह बघेल का निधन पिछले वर्ष पन्ना जिले के देवेन्द्रनगर थाने में पदस्थापना के दौरान बीमारी के कारण कार्डियक अरेस्ट से हो गया था।

ई-टोकन से खाद बुकिंग में परेशानी, रामपुर बघेलान के किसान परेशान, रामशंकर पयासी ने प्रशासन से समाधान की मांग की

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। खरीफ सीजन के बीच रामपुर बघेलान क्षेत्र में खाद की बुकिंग को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कृषि विभाग द्वारा खाद वितरण को आसान, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-टोकन प्रणाली तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है किसान खाद के लिए ऑनलाइन ई-टोकन बुक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें समय और मेहनत दोनों का नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों का कहना है कि खेती के महत्वपूर्ण समय में खाद की आवश्यकता होती है लेकिन ई-टोकन प्रणाली में आ रही तकनीकी बाधाओं के कारण उन्हें खाद मिलने में देरी हो रही है इससे फसल की बुआई और अन्य कृषि कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है कई किसान लगातार ऑनलाइन बुकिंग का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सर्वर समस्या और तकनीकी खामियों के चलते उन्हें सफलता नहीं मिल रही है कृषि विभाग ने खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और किसानों को सुविधा देने के लिए ई-टोकन व्यवस्था लागू की थी इसका उद्देश्य था कि किसान घर बैठे खाद की उपलब्धता और वितरण प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें लेकिन वर्तमान में तकनीकी दिक्कतों के कारण यही व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामशंकर पयासी ने किसानों की इस समस्या को गंभीर बताते हुए प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के समय पर खाद उपलब्ध होना बेहद जरूरी है यदि बुकिंग व्यवस्था में समस्या बनी रही तो इसका सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ सकता है। रामशंकर पयासी ने कहा कि प्रशासन को ई-टोकन प्रणाली की तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए साथ ही जब तक ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह सुचारू नहीं हो जाती, तब तक किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि उन्हें खाद के लिए परेशान न होना पड़े।

सतना में ग्रामीणों ने कलेक्टर की गाड़ी घेरा,45 मिनट तक रुका काफिला, एसडीएम-तहसीलदार के खिलाफ लगाए नारे

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले के रामपुर बघेलान तहसील कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के बाद अचानक हंगामे की स्थिति बन गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की गाड़ी को घेर लिया और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की ग्रामीणों का आरोप था कि तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और मनमानी के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है जानकारी के अनुसार जनसुनवाई समाप्त होने के बाद जैसे ही कलेक्टर तहसील परिसर से रवाना होने लगे वहां पहले से मौजूद महिलाओं सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका वाहन रोक लिया ग्रामीणों ने एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याएं सामने रखीं स्थिति को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस स्वयं वाहन से उतरकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनकी बात सुनने का प्रयास किया लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के शोर-शराबे के कारण संवाद में परेशानी हुई। मौके पर सूचना मिलने के बाद पुलिस बल पहुंचा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया करीब 45 मिनट तक चली समझाइश और मशक्कत के बाद भीड़ को शांत कराया गया जिसके बाद कलेक्टर का काफिला तहसील परिसर से रवाना हो सका। ग्रामीणों का मुख्य आक्रोश लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों, सरकारी राशन वितरण में कथित अनियमितताओं और तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर था जनसुनवाई के दौरान भी ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर शिकायतें दर्ज कराई थीं।

सतना में अब हर मंगलवार होगी अनिवार्य जनसुनवाई, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से सतना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं आदेश के अनुसार जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अब प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अनिवार्य रूप से जनसुनवाई आयोजित की जाएगी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनुविभाग स्तर पर पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) और तहसीलदारों द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों का समय-सीमा में निराकरण नहीं किया जा रहा है इसके कारण आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाएं और प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने कार्यालय के मीटिंग हॉल में प्रत्येक मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित करेंगे इस दौरान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनसुनवाई में पहुंचने वाले आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और नियमानुसार उनका त्वरित एवं प्रभावी निराकरण किया जाए उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल आवेदन लेने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि शिकायतों के समाधान के लिए वास्तविक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए और लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत किया जाए साथ ही आवेदकों को उनके प्रकरणों की प्रगति और कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा आम नागरिकों को सुगम और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराना है इसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करें नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बरसते पानी में कांग्रेस का प्रदर्शन

मझगवां एसडीएम कार्यालय का घेराव, सतना-चित्रकूट मार्ग निर्माण की मांग तेज

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवां में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बारिश के बीच हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आशुतोष द्विवेदी ने किया प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न जनसमस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी सतना-मैहर के पूर्व अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने कहा कि यदि लंबे समय से लंबित सतना से चित्रकूट मार्ग का निर्माण और सुधार कार्य जल्द शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे आंदोलन किए जाएंगे दिलीप मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से खराब सड़क व्यवस्था से परेशान है उन्होंने प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की साथ ही उन्होंने दिल्ली में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा की उन्होंने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई उन्होंने आरोप लगाया कि समस्याओं के समाधान की बजाय आंदोलन करने वालों पर कार्रवाई की बात की जाती है उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मांगें पूरी नहीं हुईं तो अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने प्रमुख रूप से सतना-चित्रकूट मार्ग की मरम्मत और जांच, मझगवां नगर की बंद पड़ी सड़क का निर्माण, पिंडरा से खोही सड़क निर्माण, इंडो न्यूक्लियर एथेनॉल प्लांट से होने वाले प्रदूषण पर रोक, मझगवां बाजार की नालियों की सफाई, कन्या हाई स्कूल के सामने ब्रिक्स लगाने सहित कई मांगें रखीं। इसके अलावा मझगवां बाजार से पुराने पोस्ट ऑफिस होते हुए मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण, कस्बे की पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने जहां पानी नहीं पहुंच रहा वहां अतिरिक्त बोर कराने और नई पानी टंकी निर्माण की मांग भी की गई कांग्रेस नेताओं ने मझगवां पंचायत द्वारा पिछले चार वर्षों में खर्च की गई राशि विशेषकर टैक्सेशन राशि से हुए कार्यों की जांच कराने की मांग भी उठाई प्रदर्शन के दौरान जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी मवासी, पूर्व संगठन मंत्री प्रदीप समदरिया सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में नीरज त्रिपाठी जैतवारा, बृजेश गर्ग सोनू, उप सरपंच सफीक, राजू सौदागर, संतोष तिवारी, अवध नरेश शर्मा, योगेश पांडेय, विजय पांडेय, चिंतन नामदेव, बेटालाल मवासी, बगड़ प्रजापति, दीपेंद्र सिंह दीपू, महेश कोल, श्यामा बाई माई सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।